राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 322 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, रविवार ,30 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

अनाथ बच्चों को पालेगा पीएम केयर्स फंड; मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और उच्च शिक्षा के कर्ज की होगी व्यवस्था

नई दिल्ली। कोरोना के रूप में आई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन्हें सरकार का पूरा साथ मिलेगा। यूं तो केंद्र की ओर से राज्यों को ऐसे बच्चों के लिए प्रबंध करने को कहा गया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में एकमुश्त 10 लाख की मदद जैसे कदम शामिल हैं। उच्च शिक्षा के लिए ऋण भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश बच्चों की मदद व संरक्षण के लिए सब कुछ करेगा ताकि उनका समुचित विकास हो और वे आगे चलकर परिपक्व नागरिक बनें। उल्लेखनीय है कि मोदी

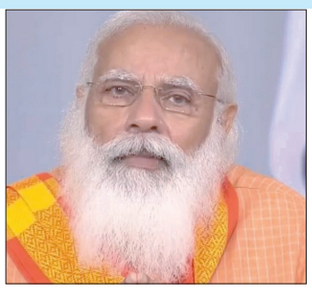

सरकार के दूसरे कार्यकाल का रविवार को दो साल पूरा हो रहा है। इससे ठीक पहले सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से अनाथ बच्चों के लिए घोषणा करेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार विमर्श के बाद कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की मदद और जीवनयापन के बारे में कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि जिन बच्चों ने माता-पिता या संरक्षक खोए हैं और मुश्किल में हैं, उनकी देखभाल करना और उन्हें सुनहरा भविष्य देना हम सब की समाज की जिम्मेदारी है।

घोषणा के मुताबिक पीएम केयर्स के योगदान से एक विशेष योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख का कोष सृजित किया जाएगा। जब बच्चा 18 वर्ष का होगा, उसे इस कोष से पांच साल तक मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वह अपनी जरूरतों और उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। 23 की उम्र होने पर उसे इस कोष की 10 लाख रुपये की रकम एकमुश्त दी जाएगी, ताकि वह अपनी निजी और व्यवसायिक जरूरतें पूरी कर सके।

पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार – 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का नजदीक के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में होता है, तो उसकी फीस आरटीई नियमों के मुताबिक पीएम केयर्स से दी जाएगी। इतना ही नहीं पीएम केयर्स बच्चे की यूनीफार्म और कापी किताबों का भी खर्च उठाएगा। 11 से 18 वर्ष के बच्चों का एडमीशन किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में कराया जाएगा। अगर बच्चा किसी संरक्षक के साथ रहता है, तो उसका एडमीशन नजदीक के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में कराया जाएगा।

उच्च शिक्षा ऋण का ब्याज देगा पीएम केयर्स– माता-पिता गंवाने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण लेने में मदद की जाएगी। मौजूदा योजनाओं के मुताबिक शिक्षा ऋण लेने में मदद की जाएगी और इस ऋण का ब्याज पीएम केयर्स से दिया जाएगा। इसके अलावा भी केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को वैकल्पिक तौर पर अंडर ग्रेजुएट या वोकेशनल कोर्स के लिए ट्यूशन फीस या कोर्स की फीस के बराबर छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो बच्चे मौजूदा योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी नहीं होंगे, उन्हें पीएम केयर्स से उसके बराबर ही छात्रवृत्ति दी जाएगी।

पांच लाख का होगा स्वास्थ्य बीमा– ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बीमा का प्रीमियम 18 वर्ष की आयु तक पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा।

बंगाल के कल्याण और विकास के लिए मोदी के पैर छूने को भी तैयार– ममता बनर्जी

कोलकाता । भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को बुलाने के फैसले को वापस ले और वरिष्ठ नौकरशाह को कोविड-19 संकट के दौरान लोगों के लिए काम करने की इजाजत दे.

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिये हर कदम पर मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे अब भी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार को पचा नहीं पाए हैं. बनर्जी ने आगे कहा कि अगर बंगाल की वृद्धि और विकास के लिये उनसे मोदी के चरण छूने को कहा जाएगा तो वह इसके लिये तैयार हैं.

उन्होंने कहा, क्योंकि आप (मोदी और शाह) भाजपा की हार (बंगाल में) पचा नहीं पा रहे हैं, आपने पहले दिन से हमारे लिये मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी. मुख्य सचिव की क्या गलती है? कोविड-19 संकट के दौरान मुख्य सचिव को वापस बुलाना दिखाता है कि केंद्र बदले की राजनीति कर रहा है.

चक्रवात से हुए विनाश पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहने के कारण हो रही आलोचना के बारे में बनर्जी ने कहा, यह बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली थी. भाजपा नेताओं को इसमें क्यों बुलाया गया? उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ दिनों के दौरान चक्रवात का सामना करने वाले राज्यों गुजरात और ओडिशा में हुई ऐसी ही समीक्षा बैठकों में विपक्ष के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था.

फोर्डा ने की एक जून को रामदेव के खिलाफ़ देशभर में काला दिवस मनाने की घोषणा

नई दिल्ली । बाबा रामदेव द्वारा टीकाकरण अभियान और ऐलोपैथिक डॉक्टरों पर दिए गए बयान को लेकर डाक्टरों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आइएमए के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन आफ रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन इंडिया (फोर्डा) ने भी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फोर्डा के अध्यक्ष डाक्टर मनीष ने बताया कि संस्था से जुड़े देश भर के सभी रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) रामदेव के खिलाफ देशभर में एक जून को काला दिवस मनाते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे।

काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे स्वास्थ्यकर्मी– इस दौरान कोरोना ड्यूटी में लगे सभी डाक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी अपनी पीपीई किट पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। साथ वाट्सएप पर अपनी डीपी को भी काला रखेंगे। इस दौरान मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए सभी आरडीए को पत्र भेज दिया गया है। डा मनीष ने आगे कहा कि देशभर के डाक्टर, पत्रकार, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और शिक्षक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं।

वहीं, रामदेव के द्वारा अपने गैरजिम्मेदाराना बयानों से सरकार के टीकाकरण अभियान के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए फोर्डा सरकार से रामदेव के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी आयुर्वेद सहित कभी भी किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ़ नहीं रही है। इसलिए एलोपैथिक डाक्टरों के खिलाफ दिया गया रामदेव का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

कोरोना के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कोविड पॉजिटिव होने पर टल गया था मामला

नई दिल्ली । देशभर में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसकी वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी. अब वह कोरोना से रिकवर हो चुके हैं इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने कोविड महामारी के दौरान जरूरी चीजों और सेवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने से संबंधित स्वत-संज्ञान मामले की सुनवाई होनी थी, जिसे पीठ के एक न्यायाधीश के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया. कोरोना मैनेजमेंट के स्वतः संज्ञान मामले पर तीन जजों की बेंच ने 13 मई को सुनवाई की तारीख तय की थी.

इससे पहले कोरोना संकट की गंभीर स्थिति का जायजा लेते हुए 8 मई को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि राज्यों में बिना किसी रुकावट के मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी नीतियों में काफी सुधार की जरूरत है. हाल के दिनों में देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते कई कोरोना मरीजों की मौत हो गई.

इसी को देखते हुए,जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 मई को 12-सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और उनकी सिफारिश करेगी. कोर्ट ने कहा था कि ये टास्क फोर्स पारदर्शी और पेशेवर आधार पर कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी, साथ ही वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगी. इसमें शामिल 10 सदस्य देश के जाने-माने डॉक्टर और दो सदस्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे.

इधर, बीते दिन एक अन्य मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण इतने बड़े देश में कितने बच्चे अनाथ हो गए और इसी के साथ उसने राज्य प्राधिकारियों को उनकी तत्काल पहचान करने और उन्हें राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया. न्यायालय ने राज्य सरकार से सड़कों पर भूख से तड़प रहे बच्चों की व्यथा समझने के लिए कहा और जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि अदालतों के किसी भी अगले आदेश का इंतजार किए बिना फौरन उनकी देखभाल की जाए. न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जिला प्रशासन को शनिवार शाम तक अनाथ बच्चों की पहचान करने और उनकी जानकारियां राष्ट्रीय बाल अपराध संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए. कोर्ट ने यह आदेश स्वत-संज्ञान के एक लंबित मामले में न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की अर्जी पर दिया.

शहीद मेजर की पत्नी ने ज्वॉइन की इंडियन आर्मी

जम्मू, (एजेंसी)। पुलवामा में शहीद अपने पति मेजर विभूति शंकर डौंडियाल के पदचिह्नों पर चलते हुए निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गईं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में उनके कंधों पर स्टार लगाए।

रक्षा मंत्रालय, उधमपुर के जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस समारोह का एक संक्षिप्त वीडियो साझा किया है। पीआरओ उधमपुर ने ट्वीट किया, पुलवामा में प्राण न्योछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर ड-डौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पत्नी निकिता कौल ने सेना की वर्दी पहन ली। यह उनके लिए गर्व का मौका होगा क्योंकि सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट वाई के जोशी ने उनके कंधे पर स्टार लगाए।

मेजर डौंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को लेकर उन्हें शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया था। इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने सेना और शहीद सैन्यकर्मी की पत्नी की सराहना की है। स्वप्निल पांडे ने लिखा आपको पता है यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैनिक न भी रहे, लेकिन सेना उनके परिवारों को कभी अकेलापन का अहसास नहीं होने देती है।

समकालीन समय में महत्वपूर्ण अंतर को भरता है क्वाड : जयशंकर

वाशिंगटन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का अनौपचारिक क्वाड समूह समकालीन समय में उपजे बेहद महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है, और नयी दिल्ली इसमें (क्वाड में) अपनी सदस्यता को लेकर स्पष्ट है। क्वाड का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के बीच सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। शुक्रवार को यहां अपनी अधिकांश बैठकों के खत्म होने के बाद भारतीय पत्रकारों के एक समूह को उन्होंने बताया, समकालीन समय में, जहां वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरतें हैं जिन्हें एक देश द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, उभरे एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर को आज क्वाड पाटता है।

इस अंतर को किसी एक द्विपक्षीय रिश्ते से भी दूर नहीं किया जा सकता और बहुपक्षीय स्तर पर भी इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जयशंकर 20 जनवरी को जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से देश

की यात्रा पर आने वाले पहले भारतीय कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड में अपनी सदस्यता को लेकर भारत का रुख साफ है। साथ ही कहा कि वह पिछले कई वर्षों से इस समूह की प्रगति में व्यक्तिगत तौर पर शामिल रहे हैं तब से जब वह भारत के विदेश सचिव थे। जयशंकर ने कहा, हम क्वाड के सदस्य हैं। हम जब किसी भी चीज के सदस्य होते हैं तो हम उसे लेकर बहुत उत्सुक होते हैं नहीं तो हम इसके सदस्य ही नहीं होते। क्वाड पर हमारा रुख साफ है। विदेश मंत्री और बाइडन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के बीच जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें क्वाड का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की।

मंत्री ने कहा, क्वाड पहले भी और अब भी हाल के वर्षों में नौवहन सुरक्षा एवं संपर्क पर चर्चा करता है। इसने प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला और टीका उत्पादन के मुद्दों पर भी चर्चा शुरू कर दी है। इसके अलावा नौवहन सुरक्षा को भी लेकर कुछ मुद्दे हैं। कुल मिलाकर, कई तरह के मुद्दे हैं। किसी देश का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि बहुत, बहुत चिंताएं हैं जिन्हें किसी न किसी को तो देखना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि बड़े देश इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, देशों का समूह मिलकर साझा हितों एवं स्थितियों को लेकर चर्चा करे तो अधिकांश मुद्दों का हल हो जाएगा। उन्होंने कहा, तो हम इस तरह क्वाड को देखते हैं। क्वाड कई देशों के हितों के सम्मिलन की अभिव्यक्ति है। यह कई मायनों में दुनिया की समकालीन प्रकृति का प्रतिबिंब हैङ्घजहां यह एक समुच्चय नहीं है, आप जानते हैंङ्घकिसी न किसी स्तर पर हमें शीतयुद्ध को पीछे छोड़ना होगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बुलाने से पैदा होगी अराजकता : कांग्रेस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को वापस बुलाए जाने को लोकतंत्र और सहकारी संघवाद पर हमला करार देते हुए शनिवार को कहा कि ऐसे कदम से अराजकता पैदा होगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि बंदोपाध्याय को तीन महीने का सेवा विस्तार देने के चार दिनों बाद ही वापस बुलाने का फैसला क्यों किया गया उन्होंने एक बयान में कहा मोदी सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दुर्भावनापूर्ण एवं मनमाना ढंग से वापस बुलाए जाने ने पूरे देश की चेतना को स्तब्ध कर दिया है। यह इस मायने में और भी गंभीर है कि चार दिनों पहले मोदी सरकार ने ही मुख्य सचिव को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया था। केंद्र का यह कदम लोकतंत्र और सहकारी संघवाद पर हमला है तथा ऐसे कदम से देश में अराजकता पैदा होगी। उन्होंने कहा यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठाराघात है। अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसका खुलासा करेंगे कि मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने के चार दिनों के बाद ही उन्हें किस कारण से वापस बुलाया गया केंद्र सरकार के कदमों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह हाल ही में निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करना चाहती है।

सोशल मीडिया फैक्ट चेकर्स पर केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, मोदी के खिलाफ नफरत फैलाना है एजेंडा

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों पर हमला करते हुए कहा कि, उन्हें किसी भी हालत में सरकार के जरिए बनाए गए नए आईटी नियमों को मानना होगा और उसी मुताबिक देश में काम करना होगा. वहीं इन सोशल मीडिया कंपनियों को अब से सरकार के लिए ज्यादा जवाबदेह होना होगा. प्रसाद ने यहां बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्विटर पोस्ट को **Manipulated** मीडिया टैग करने को लेकर भी हमला किया जो कांग्रेस का कथित टूलकिट मामला था. उन्होंने कहा कि, सोशल मीडिया जाएंट को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए.

भारत सरकार ने यहां सोशल मीडिया कंपनी जैसे ट्विटर और फेसबुक से कहा है कि उन्हें नए नियमों को मानना होगा और मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और शिकायत अधिकारी की जानकारी आईटी मंत्रालय के साथ शेयर करनी होगी. इसमें सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने तो हां कर दी है लेकिन ट्विटर ने अब तक इसपर अपनी कोई राय नहीं दी है. नए नियमों में कंपनियों को उन पदों की उत्पत्ति का खुलासा करने की भी आवश्यकता है जो परेशानी पैदा कर सकते हैं.

आईटी मंत्रालय ने कहा कि, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के हित में सरकार केवल उन संदेशों की उत्पत्ति जानना चाहती है जो हिंसा, दंगे, आतंकवाद, बलात्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं. अपने इंटरव्यू में कानून मंत्री के रूप में, मैं सभी सोशल मीडिया कंपनियों से कहना चाहता हूं कि भारत की डिजिटल संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

फैक्ट चेकर्स मोदी के खिलाफ फैलाना चाहते हैं एजेंडा– फेसबुक ने आईटी नियमों को देखते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में प्रसाद ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार आलोचना से नहीं डरती, बल्कि ट्विटर के फैक्ट-चेकर्स की मंशा पर सवाल उठाती है. उन्होंने आगे कहा कि, एक फैक्ट चेकर का एजेंडा फिलहाल मोदी के खिलाफ नफरत फैलाना है. हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं. हमारे पीएम को साल 2001 से ही पूरी दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां यहां केवल सिर्फ एक पक्ष को ही नहीं प्रमोट कर सकती.

एक अमेरिकी लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में, भारत में हर तरह से व्यापार करें. लेकिन भारत के कानूनों और संविधान का पालन करें. हमारी संसद और संस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी अन्य देश की. प्रसाद ने आगे कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां आतंकवाद से संबंधित मामलों में अमेरिका या ब्रिटेन की सरकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर संदेशों की उत्पत्ति पर आसानी से डेटा की आपूर्ति करती हैं

पाक व अन्य देशों से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने मांगे आवेदन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर जारी विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटीफिकेशन जारी कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आर्मंत्रित किए हैं। ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे। सूत्रों के मुताबिक अभी नए सीएए के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीएए कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने प्रावधान किया गया था. लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं है। इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जब देश में सीएए लागू करने की पहल की तो इसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। मुस्लिम संगठनों, कई गैर सरकारी संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला बताते हुए इसका विरोध किया था। इसके बाद देश-व्यापी प्रदर्शन हुए थे। इस कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन किया गया था। गृहमंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य हैं जो गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा में रह रहे हैं।

कार्टून

कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। यह लोग देश में नागरिकता को लेकर बनाए गए एक कानून का विरोध कर रहे थे।

जयशंकर के साथ भारत-चीन सीमा की स्थिति पर हुई चर्चा : अमेरिकी विदेश मंत्री

वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उसकी बैठक सार्थक रही और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत-चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान पर चर्चा की तथा साझा चिंताओं के क्षेत्रों पर साथ मिलकर काम करने का प्रण किया। जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह 20 जनवरी को जो बाइडन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद देश की यात्रा पर आए भारत के पहले मंत्री हैं। उन्होंने शुक्रवार को ब्लिंकन से मुलाकात की। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ब्लिंकन ने विदेश मंत्रालय में जयशंकर का स्वागत किया और अमेरिका-भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की अमेरिकी प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। ब्लिंकन ने कहा, डॉ. एस जयशंकर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका के कोविड-19 राहत प्रयासों समेत आर्थिक प्राथमिकताओं, भारत-चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान के लिए हमारे सहयोग पर आज रचनात्मक बातचीत की। ब्लिंकन ने विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया, मित्र के तौर पर हम साझा चिंताओं के इन क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं, जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर ब्लिंकन के साथ सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा, हिंद-प्रशांत और क्वाड, अफगानिस्तान, म्यांमा, यूएनएससी मामलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी बातचीत की।

जयशंकर ने कहा, भारत-अमेरिका के बीच टीकों की साझेदारी पर भी चर्चा की जिसका मकसद टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस वक्त अमेरिका द्वारा जताई मजबूत एकजुटता की सराहना करते हैं। आज की बातचीत ने हमारी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के हमारे एजेंडे को और मजबूत किया है। भारतीय पत्रकारों के एक समूह के सवाल के जवाब में जयशंकर ने इसका जिक्र नहीं किया कि क्या खासतौर से चीन पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, हमने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देश चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। चीन की सेना की नजर भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र पर है। अमेरिका को भारत का रणनीतिक साझेदार बताते हुए जयशंकर ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों ने अपनी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक में रूस से अरबों डॉलर की एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की भारत की योजना के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने कहा कि भारत-चीन सीमा पर घटनाक्रमों पर ही चर्चा की गई। उन्होंने कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार, दोनों नेताओं ने कोविड-19 राहत प्रयासों, क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की कोशिशों और जलवायु परिवर्तन से निपटने की साझा प्रतिबद्धता तथा संयुक्त सुरक्षा परिषद समेत अन्य मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्राइस ने कहा, ब्लिंकन और जयशंकर ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों, बर्मा में तख्तापलट और अफगानिस्तान के लिए सहयोग जारी रखने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर सहयोग जारी रखने का भी संकल्प लिया। इससे पहले थॉम्पसन ने पत्रकारों को बताया कि यह बैठक साझेदारी और आगामी वर्षों में इसे मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है। उन्होंने कहा, ब्लिंकन और जयशंकर के बीच आज हुई बैठक महामारी शुरू होने के बाद से वाशिंगटन में पहली व्यक्तिगत मुलाकातों में से एक है। यह बैठक भारत के साथ हमारे संबंधों की गहराई को दिखाती है। भारत को हम क्षेत्र तथा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक के रूप में देखते हैं।

भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना अमेरिका, मॉरीशस तीसरे स्थान पर

नयी दिल्ली। अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) का दूसरा प्रमुख स्रोत हो गया है और उसने मॉरीशस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में अमेरिका से भारत को 13.82 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। इस दौरान सिंगापुर से प्राप्त एफडीआई 17.41 अरब डॉलर रहा।

वर्ष के दौरान मॉरीशस से 5.64 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से (4.2 अरब डॉलर), केमैन आइलैंड (2.79 अरब), नीदरलैंड (2.78 अरब), ब्रिटेन (2.04 अरब), जापान (1.95 अरब डॉलर), जर्मनी (66.7 करोड़ डॉलर) और साइप्रस से 38.6 करोड़ डॉलर का एडीआई आया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत में एफडीआई 19 प्रतिशत बढ़कर 59.64 अरब डॉलर के बराबर रहा। सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस दौरान कई नीतिगत सुधार , निवेश की सुविधा तथा कारोबार में और आसानी के लिए कई कदम उठाये हैं। यदि इसमें पहले के एफडीआई निवेशकों द्वारा पूंजी और लाभ के पुनर्निवेश को जोड़ दे तो वर्ष 2020-21 में कुल एफडीआई 81.72 अरब डॉलर के बराबर रहा जोकि 2019-20 के 74.39 अरब डॉलर से दस प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंप्यूटर, सॉफ्टेयर और हार्डवयर क्षेत्र 26.14 अरब डॉलर के निवेश के साथ एफडीआई आकर्षित करने के मामले में सबसे ऊपर रहा। उसके बाद बुनियाद ढांचा (7.87 अरब डॉलर) और सेवा क्षेत्र (पांच अरब डॉलर) का स्थान रहा।

अमेरिका ने माना, अफगानिस्तान पर बातचीत में भारत का है अहम हिस्सा!

वाशिंगटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि जब अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा की बात आती है तो भारत इस बातचीत का अहम हिस्सा है। जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के साथ बैठक के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठा क्योंकि यह एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा, एक बार वहां से अमेरिकी सैनिक चले जाएं फिर जो संभावित परिदृश्य है उससे हमें यकीनन सरोकार है, उससे अफगानिस्तान को भी सरोकार है, अमेरिका के लिए भी वह मायने रखता है और क्षेत्रीय स्तर पर भी उसका व्यापक असर होगा।

दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अप्रैल माह में घोषणा की थी कि इस वर्ष 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सारे सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे और इसी के साथ देश का सबसे लंबे समय तक चला युद्ध समाप्त हो जाएगा। यहां भारतीय संवाददाताओं के एक समूह से बातचीत में जयशंकर ने कहा कि प्रत्येक बैठक में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मुद्दा था कि भारत की भूमिका क्या है? मेरा मतलब है कि भारत का हित है, भारत का प्रभाव है, भारत का वहां इतिहास है। हम क्षेत्र के एक देश हैं। हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जयशंकर ने कहा, तो अमेरिका में और कई देशों में साफ तौर पर ऐसा मानना है कि जब आप अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करते हो तो भारत उस बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, इस बात पर चर्चा हुई कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए,क्या नहीं होना चाहिए।

गाजा सिटी में इजराइल के हमले बंद होने के बाद फिलीस्तीन के लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं, और वे समुद्र में मस्ती करते देखे जा रहे हैं।

भारतीय नागरिक सिंगापुर हवाईअड्डे पर नहीं हुआ कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

सिंगापुर। नेपाल से 25 अप्रैल को सिंगापुर आयी 32 वर्षीय भारतीय नागरिक के चांगी हवाईअड्डे पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका नहीं है क्योंकि उनके मामले का और हवाईअड्डे के टर्मिनल तीन में संक्रमित पाए गए यात्रियों के बीच कोई फाइलोजेनेटिक (वंशावली) संबंध नहीं है। फाइलोजेनेटिक जांच से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या संक्रमण के मामलों का आपसी संबंध है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसकी जांच में यह पुष्टि हुई है कि सोनल वड्डु के मामले और चांगी हवाईअड्डु के टर्मिनल तीन पर संक्रमित पाए लोगों के बीच कोई फाइलोजेनेटिक संबंध नहीं है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की एक खबर के अनुसार, वड्डु ने कहा था कि वह भारत में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थीं। इस मामले ने फेसबुक पर एक सवाल पर उनके जवाब का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद तूल पकड़ा। उन्होंने कहा था कि इसकी अधिक संभावना है कि वह चांगी हवाईअड्डे पर संक्रमित हुईं। अंग्रेजी के दैनिक अखबार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा, रवाना होने से पहले की जांच या गंतव्य पर पहुंचने की जांच में संक्रमित न पाए जाने का यह मतलब नहीं होता कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से मुक्त है क्योंकि हो सकता है कि ये जांच करवाने से पहले ही वह संक्रमण की चपेट में आ चुका हो।

चीन में नहीं थमा है कोरोना का कहर, 16 नये मामलों की हुई पुष्टि

बीजिंग। चीन में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 16 नये मामलों की पुष्टि हुई है। समझा जाता है कि नये संक्रमितों में शामिल दो अधिकारी स्थानीय तौर पर संक्रमण की चपेट में आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) के मुताबिक स्थानीय रूप से प्रसारित दो मामले दक्षिण में स्थित गुआंगदोंग प्रांत के हैं जो हांगकांग से सटा हुआ है।

वेस्ट बैंक में प्रदर्शन के दौरान इजराइली सैनिकों ने की गोलीबारी, फिलिस्तीनी युवक की मौत

यरूशलम। इजराइल के कब्जे वाले वाले वेस्ट बैंक में रिहायशी इलाके में विस्तार के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान इजराइली सेना की गोलीबारी में शनिवार को फलस्तीन के एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह प्रदर्शन बेइटा कस्बे के निकट एक चौकी बनाने के विरोध में हुआ। फलस्तीनी इसे इजराइल के भूमि हथियाने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं।

सैकड़ों की संख्या में लोग एक पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए। बड़ी संख्या में फलस्तीनी युवाओं ने टायर जलाएऔर गोलियां, रबर की गोलियां तथा आंसू गैस के गोले दागने वाले सैनिकों पर उन्होंने पथराव किया। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सेना की गोलीबारी में 26 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई जबकि पांच प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इजराइली सेना ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। यह संघर्ष इजराइल और फलस्तीन के विद्रोही संगठन हमास के बीच 11 दिन चले युद्ध के बाद हुआ है। एक सप्ताह पहले बंद हुई लड़ाई में 250 से अधिक लोग मारे गए जिनसे से अधिकतर लोग फलस्तीन से थे।

इंसानों में मिला है कुत्तों का कोरोना वायरस, क्या चिंता करने की है जरूरत

कैम्ब्रिज (ब्रिटेन)। वैज्ञानिकों ने निमोनिया से पीड़ित कुछ लोगों में कुत्तों में पाए जाने वाले एक नयी तरह के कोरोनावायरस का पता लगाया है। यह कहने, सुनने में भले खतरनाक लग सकता है, लेकिन इसका विश्लेषण करने के बाद लगता है कि इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलेशिया के सरवाक के एक अस्पताल में आठ लोगों में कुत्तों का कोरोनावायरस पाए जाने के बारे में अत्यधिक सम्मानित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने नैदानिक ????संक्रामक रोगों से संबंधित विभाग को सूचित किया है। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि कुत्ते इंसानों में कोरोनावायरस फैला सकते हैं? सबसे पहले स्पष्ट करने वाली बात यह है कि कुत्तों का कोरोनावायरस क्या है। यह जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि यह सार्स-कोवी-2, जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है,से काफी अलग है।

कोरोनावायरस परिवार को वायरस के चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोरोनावायरस। सार्स-कोवी-2 बीटाकोरोनावायरस समूह में आता है, जबकि कुत्तों के कोरोनावारस पूरी तरह से अलग अल्फाकोरोनावायरस समूह से हैं। वैज्ञानिक लगभग 50 वर्षों से कुत्तों के कोरोनावायरस के बारे में जानते हैं। इस अवधि के अधिकांश समय में ये वायरस अपने एक अनजान अस्तित्व के साथ मौजूद रहे और केवल पशु चिकित्सक और कभी-कभी कुत्तों को पालने वाले लोग इनमें रूचि रखते थे। इन वायरस के इन्सानों को संक्रमित करने के बारे में पिछली कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब अचानक दुनिया में सब तरफ कोरोनावायरस पर सबकी नजर रहने से उन जगहों पर भी कोरोनावायरस की मौजूदगी के निशान मिल रहे हैं, जहां इन्हे पहले कभी नहीं देखा गया था। हाल ही में लोगों में पाया गया कुत्तों का कोरोनावायरस संक्रमण दरअसल इस दिशा में की जा रही गंभीर खोज का नतीजा था। जिन लोगों को इस खोज का हिस्सा बनाया गया था वह काफी समय पहले ठीक हो चुके थे।

वैज्ञानिक विशेष रूप से सिर्फ कुत्तों के कोरोनावायरस की तलाश नहीं कर रहे थे, शोधकर्ता एक ऐसा परीक्षण विकसित करने की कोशिश कर रहे थे जो एक ही समय में सभी प्रकार के कोरोनावायरस का पता लगा सके - एक तथाकथित पैन-सीओवी परीक्षण। प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए वायरस के नमूनों पर परीक्षण के काम करने की पुष्टि के बाद, उन्होंने मलेशिया के एक अस्पताल में भर्ती रहे निमोनिया के 192 रोगियों के नमूनों पर इसका परीक्षण किया। इनमें से नौ नमूनों का परिणाम कोरोनावायरस के लिए पॉजिटिव आया। इस संबंध में और जांच करने पर पता चला कि उपरोक्त नौ नमूनों में से पांच सामान्य मानव कोरोनावायरस थे जिससे सर्दी जुकाम हो सकता है।लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से, चार नमूने कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोनावायरस के थे। इसी अस्पताल के मरीजों की और जांच करने पर चार और पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोनावायरसों के बारे में अधिक जानने के प्रयासों के तहत शोधकताओं ने इन सभी आठ मलेशियाई रोगियों के नाक और गले के नमूनों की जांच का अध्ययन किया। यह जानने के लिए कि क्या कोई जीवित वायरस मौजूद है, प्रयोगशाला में इन नमूनों को कुत्ते की कोशिकाओं में डाला गया।

एक ही नमूने से वायरस को अच्छी तरह से दोहराया गया, और वायरस के कणों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके देखा जा सकता था। वैज्ञानिक वायरस के जीनोम को अनुक्रमित करने में भी सक्षम थे। विश्लेषण में पाया गया कि कुत्तों में पाया जाने वाला कोरोनावायरस कुछ अलग अल्फाकोरोनावायरस - जिसमें सूअर और बिल्लियाँ भी शामिल थे - से निकटता से संबंधित था और यह भी पता चला कि इसे पहले कहीं और पहचाना नहीं गया था। आगे फैलने का कोई सबूत नहीं अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मरीजों में निमोनिया के लिए कुत्तों में पाया जाने वाला यह कोरोनावायरस जिम्मेदार था? फिलहाल, हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जांच का हिस्सा बनाए गए आठ में से सात मरीज एक साथ दूसरे वायरस से भी संक्रमित थे, जो या तो एडेनोवायरस, इन्फ्लूएंजा या पैरेनफ्लुएंजा वायरस था। हम जानते हैं कि ये सभी वायरस अपने आप में निमोनिया का कारण बन सकते हैं, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि ये बीमारी के लिए जिम्मेदार थे। हम कह सकते हैं कि इन रोगियों में मिले निमोनिया का कुत्तों के कोरोनावायरस के साथ संबंध है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सिर्फ यह वायरस ही उनमें निमोनिया का कारण है।

इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि मलेशिया के इन रोगियों में पाया गया कुत्तों का कोरोनावायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका नतीजा बड़े पैमाने पर बीमारी के प्रकोप के तौर पर सामने आएगा। इस तथ्य को प्रमुखता से उठाने वाले यह स्पष्ट नहीं करते कि इनसानों में संक्रमण के यह मामले दरअसल 2017 और 2018 के हैं। ऐसे मेंइस स्रोत से कुत्तों के कोरोनावायरस के प्रकोप की संभावना और भी कम हो जाती है क्योंकि बीच के तीन से चार वर्षों में इसके आगे फैलने का कोई सबूत नहीं है। यह ऐसा समय है, जब चारों तरफ कोरोनावायरस की बात हो रही है और इससे जुड़े तमाम तरह के वायरस की खोज की जा रही है और ऐसे मेंअप्रत्याशित स्थानों से कुछ और पॉजिटिव नमूने मिलने से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें से अधिकांश केवल अध्ययन और जांच तक सीमित होंगे और इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि नए कोरोनवायरसों पर निगरानी जारी रहे और इसका विस्तार हो ताकि भविष्य में अगर कोई नयी तरह का वायरस सामने आए तो हमारे पास उसे पहचानने का हर संभव मौका हो।

अमेरिका ने चीनी कंपनी से सीफूड का आयात रोका

वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार ने उस चीनी कंपनी से सीफूड के आयात पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिस पर चालक दल के सदस्यों को गुलाम की तरह काम करने के लिए विवश करने का आरोप है जिसके चलते पिछले साल कई इंडोनेशियाई मछुआरों की मौत हुई। सीमा शुल्क तथा सीमा संरक्षण विभाग ने कहा कि वह डालियन ओशियन फिशिंग के 30 से अधिक जहाजों से जुड़े किसी भी आयात पर तत्काल रोक लगाएगा। वह अमेरिका के उस कानून के तहत यह रोक लगाएगा जिसमें ऐसे उत्पाद पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है जिनका उत्पादन गुलाम जैसी स्थितियों में काम कर रहे श्रमिकों ने किया है। गृह मंत्री एलेजांद्रो मेयरकास ने पत्रकारों से कहा, हम जबरन मजदूरी से उत्पादित किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे।

इंडोनिशिया के वेस्ट जावा में दुर्घटनाग्रस्त एक प्लेन की तलाश में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कमेटी के सदस्य।

केंद्र जल्द टीके खरीदकर राज्यों को दे : केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज से शुरू हुए सरकारी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र से गुजारिश की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द टीके खरीदकर राज्यों को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। ऐसे में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 900 केस आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1000 से भी कम केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं।

सीएम केजरीवाल ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से धीरे-धीरे लॉकडाउन खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहां एक सप्ताह के लिए निर्माण गतिविधियों और फैक्टरियों को खोले जाने की इजाजत दी गई है। संक्रमण की दूसरी लहर से बेहद प्रभावित दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया करीब छह सप्ताह से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के बाद हो रही है।

केजरीवाल ने एक कार्यक्रम से इतर कहा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 900 मामले सामने आए हैं। संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1,000 से नीचे है और संक्रमण दर में कमी आई है इसलिए हम ज्यादा गतिविधियों को शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट आए। सीएम केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में स्थित एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान केंद्र का मुआयना किया। इस केंद्र की व्यवस्था कुछ इस तरह की गई है कि लोग अपने वाहनों में बैठे-बैठे ही टीका लगवा सकेंगे।

उन्होंने कहा, इस केंद्र पर लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। लोग पैदल चलकर भी आ रहे हैं। जैसे ही हमें 18-44 उम्र समूह के लोगों के लिए टीके की आपूर्ति होती है, यह व्यवस्था उनके लिए भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने तत्काल आधार पर कोविड-19 टीके की खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने वैश्विक स्तर पर निविदा डाली है और उम्मीद करते हैं कि कुछ कंपनियां आएंगी। विभिन्न सरकारों ने वैश्विक निविदा निकाली है लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर कुछ कंपनियां हमसे संपर्क करती हैं तो यह अच्छा होगा। लेकिन मेरी समझ है कि दुनिया की कंपनियां टीकों की खरीद के लिए केंद्र सरकार से बात करना चाहती हैं।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की।

12-17 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 से 17 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका 12 वर्षीय टीया गुप्ता व रोमा रहेजा नामक बच्चों ने दायर की है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दोनो पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 4 जून तय की है। याचिकाकर्ता ने इसके अलावा अदालत से अपने माता-पिता के टीकाकरण को प्राथमिकता देने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासदेव ने तर्क रखा कि बच्चों के लिए टीकाकरण नीति बनाना जरूरी है ताकि चीजों को बहुत अलग बनाने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चों के माता-पिता का निधन हो गया है। वे अनाथ होते जा रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल से दूर रखा जा रहा है, इस आयु वर्ग के कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। याचिका में कहा कि कोविड-19 में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है उसकी रक्षा करना सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस बात के साक्ष्य है कि कोविड की दूसरी लहर में गैर-टीका लगाए गए बच्चों में एक नया अधिक शक्तिशाली कोविड स्टेन के विकसित होने की संभावना अधिक है। उन्होंने बच्चों पर तीसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव पर चिकित्सा राय का हवाला देते हुए कहा कि टीका लगाने से न केवल देश में कोविड-19 वायरस को पनपने की श्रृंखला को तोड़ने का एक प्रभावी तरीका होगा।

हरियाणा-दिल्ली बार्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में बिखराव, चढ़ूनी के अलग फेडरेशन से कई संकेत

नई दिल्ली । तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ बीते वर्ष 26 नवंबर से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं में मतभेद पहले से थे। कई बार सतह पर भी आए। अब एक बार फिर मतभेद सार्वजनिक होने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चे से अलग भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह संयुक्त किसान मोर्चे के साथ तो रहेंगे, लेकिन अपनी अलग राह पर चलते रहेंगे ।

चढ़ूनी के इस नए संगठन को लेकर अभी तक संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। मोर्चे की सात सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य और स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव इंटरनेट मीडिया पर मुखर रहते हैं, लेकिन चढ़ूनी के नए फेडरेशन को लेकर उनका कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

चढ़ूनी ने ही की थी हरियाणा में आंदोलन की शुरूआत

गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हरियाणा में अपनी अलग भारतीय किसान यूनियन है, जिसे भाकियू (चढ़ूनी) के नाम से जाना जाता है । सितंबर 2020 में चढ़ूनी ने ही सबसे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया। इसके बाद हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने चढ़ूनी सहित अन्य किसान संगठनों के नेताओं को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। लेकिन चढ़ूनी ने इस वार्ता का बहिष्कार किया। बाद में संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में हरियाणा-दिल्ली सीमा पर शुरू हुए किसान संगठनों के आंदोलन में चढ़ूनी को ज्यादा महत्व नहीं मिला।

जनवरी माह में जब चढ़ूनी ने दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया तो उनके और मध्यप्रदेश के किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी के बीच विवाद भी हुआ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी चढ़ूनी की पटरी नहीं बैठी। इसका ताजा उदाहरण हिसार में देखा गया। हिसार में राकेश टिकैत और चढ़ूनी अलग दिखाई दिए। चढ़ूनी ने टिकैत का नाम लिए बिना यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन निष्प्रभावी हो रहा है।

टिकैत की राय इससे अलग

दूसरी तरफ भाकियू (टिकैत) राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे में करीब 550 किसान संगठन शामिल हैं। सभी मिलकर आंदोलन चला रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन के निष्प्रभावी की बाबत गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो बयान आया है, यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आंदोलन प्रभावी ढंग से चल रहा है। गाजीपुर बार्डर पर हजारों किसान लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदेश में लगातार टोल फ्री करवाए जा रहे हैं। किसानों के हक में भारतीय किसान यूनियन हर संभव लड़ाई लड़ रही है।

साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को दी जमानत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को शनिवार को जमानत दे दी है। कालरा को अदालत से सशर्त जमानत मिली है। कालरा तीन जून तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने कालरा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कालरा ने व्हाइट कॉलर क्राइम को किया और मृत्यु शैय्या पर लेटे मरीजों को अत्यधिक दामों पर मेडिकल उपकरण बेचकर मुनाफा कमाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कालरा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कथित जमाखोरी करने और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 17 मई को गिरफ्तार किए गए आरोपी नवनीत कालरा की जमानत प्रदान कर दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कालरा की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि आरोपी की मंशा लोगों को ठगने और मुनाफा कमाने की थी। यह व्हाइट कॉलर क्राइम है। उसने मृत्यु शैय्या पर पड़े जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे थे। एक दिन पहले कालरा ने वरिष्ठ वकील विकास पहवा के जरिये अदालत को बताया कि उसकी लोगों को ठगने की आपराधिक मंशा नहीं थी और उसे मुकदमे की सुनवाई से पहले हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बता दें कि, हाल ही में एक छापे के दौरान कालरा के तीन रेस्टोरेंट्स - खान चाचा, टाउन हॉल तथा नेगे एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे।

जून में दिल्ली को 18+ उम्र वालों के लिए मिलेंगे सिर्फ 5.5 लाख टीके : सिसोदिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को केंद्र से जून में 18-44 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकों की 5.5 लाख डोज मिलेंगी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीकों की वितरण प्रणाली पर अड़ियल बर्ताव कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर टीकाकरण के कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया और पूछा कि निजी अस्पतालों को टीके कैसे मिल रहे हैं, जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि टीके खत्म हो गए हैं। सिसोदिया ने कहा कि जब दिल्ली सरकार कहती है कि उसे युवाओं को फ्री वैक्सीन लगानी है तो केंद्र सरकार कहती है वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल उन्हीं युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए कंपनियों से खरीदते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन दिलवा देती है। सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है, सभी राज्य सरकारें वैक्सीन का इंतजार कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन विदेशों को भेज दी, समय पर ऑर्डर नहीं किए, जिसकी वजह से सब वैक्सीन लगवाने के लिए भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बताए कि वो महामारी के समय में वैक्सीन, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स लेकर कमाई क्यों करना चाहती है उन्होंने कहा कि कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। हमने वैक्सीन आदि को टैक्स फ्री करने की मांग रखी। कई राज्यों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया, इसलिए कल वैक्सीन टैक्स फ्री करने का फैसला नहीं हो पाया। सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी दवाई है, भाजपा इससे पैसा कमाने की न सोचे। दिल्ली की विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 27 मई को 39 हजार लोगों का टीकाकरण किए जाने के बाद राजधानी में किसी भी आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का टीकाकारण शुक्रवार को पांचवें दिन भी लंबित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों को युवाओं के टीकाकरण के लिए डोज उपलब्ध नहीं मिल रही है, हालांकि, निजी अस्पतालों में इसकी कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता ने कहा कि पांच दिन हो चुके हैं, दिल्ली में युवाओं का टीकाकारण रुका हुआ है। एक तरफ राज्य युवाओं को टीका लगाने में समर्थ नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में इसकी कोई कमी नहीं है और वे एक डोज के लिए 900-1,350 रुपये तक वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है और उनके लिए भी कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। विधायक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेना चाहता है, दिल्ली में उसके लिए कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, चाहे वह 18-44 साल आयु वर्ग में हो अथवा 45 साल से अधिक आयु वर्ग का हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 27 मई को 39,020 लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि इसी दिल्ली में पहले 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण होता था। केंद्र के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के बाद से अब तक 52.84 लाख खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 36.79 लाख कोविशील्ड जबकि 16.04 लाख कोवैक्सीन की खुराक है। टीकाकरण की शुरूआत के बाद से अब तक दस मई को सबसे अधिक 1.41 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया था। आतिशी ने कहा कि अगर 18-44 साल आयु वर्ग में अगर किसी को टीका लेना है तो वह निजी अस्पतालों के माध्यम से ले सकता है।

कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही कॉकटेल ड्रग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना के इलाज में कारगर कॉकटेल ड्रग यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिल्ली में भी लांच हो गई है। एक निजी अस्पताल में 65 साल के बुजुर्ग को यह दवा दी गई। दिल्ली का यह पहला केस है, जिसमें दवा का इस्तेमाल किया गया है। 24 मई को दवा को लांच किया गया था, तब एक अन्य निजी अस्पताल में 84 साल के एक बुजुर्ग को यह दी गई थी। अन्य निजी अस्पताल में अब तक 8 मरीजों को यह दवा दी गई है। दिल्ली में कई और अस्पताल भी इस दवा के इस्तेमाल की तैयारी में जुटे हैं।

निजी अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर ने कहा कि 65 साल के कोविड मरीज को एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया। हमें खुशी है कि देश भर में कोविड मरीजों के लिए ट्रीटमेंट का लांच किया जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोविड के साथ जुड़कर इस न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वायरस की ग्रोथ रुक जाती है। हमें विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ यह इलाज बेहतर विकल्प बनेगा। माइल्ड व मॉडरेट लक्षण वाले मरीजों में बीमारी कम गंभीर होगी। इस थैरेपी को एंटीबॉडी कॉकटेल इसकारण कहा गया है, क्योंकि इसमें दो बायलॉजिकल दवाओं का मिश्रण है, जो मनुष्य के एंटीबॉडीज की तरह हैं और प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये एंटीबॉडी, बीमारी को गंभीर स्थिति तक पहुंचाने से रोकने में कारगर होंगी। एंटीबॉडी कॉकटेल को देने में औसतन एक घंटे का समय लगता है।

भीख मांगें या उधार लें लेकिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना ही होगा : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद कर्मचारियों व अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन व बकाया राशि का भुगतान न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उत्तरी एमसीडी के आयुक्त को तलब किया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने कहा आप भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे लेकिन आपको कर्मचारियों की राशि का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख तक 5 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरी एमसीडी आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में मौजूद रहेंगे। अदालत का यह निर्देश अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने अदालत को बताया कि न्यायिक आदेशों के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अवमानना शुरू करने की मांग की। अदालत ने उत्तरी एमसीडी को इस मामले में नोटिस जारी कर दो दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 मई तय की है। उत्तरी एमसीडी की और से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि वे वेतन मामलों में रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने वेतन और पेंशन के लिए पैसे वितरित करने की कोशिश की है और अप्रैल तक वेतन का भुगतान कर दिया है। खंडपीठ ने उनके तर्क को खारिज करते हुए कहा, हम इस बारे में चिंतित नहीं हैं। आप भीख मांगते हैं, उधार लेते हैं या चोरी करते हैं लेकिन राशि का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने इससे पहले भी सभी श्रेणियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बकाया राशि स्पष्ट करने के लिए समय बढ़ाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने सभी बकाया राशि को मंजूर करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया था। अदालत ने दिल्ली की तीनों एमसीडी को 5 अप्रैल को या उससे पहले सभी पूर्व कर्मचारियों और सभी श्रेणियों के सेवारत कर्मचारियों की पेंशन और वेतन के सभी बकाया राशि को जारी करने निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि तीनों एमसीडी आयुक्त राशि का भगतान समय पर हो यह सुनिश्चित करे। अदालत ने न्यूज पेपरों में प्रकाशित कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डाक्टरों की धमकी पर भी संज्ञान लिया था कि यदि पिछले वर्ष मार्च माह से रूके पूरे वेतन का भुगतान न हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे।

दिल्ली में कर्फ्यू को नाकाफी बताने वाले व्यापारी अब पूरा अनलॉक न होने से खफा

नई दिल्ली। राजधानी में पिछले महीने से चले आ रहे लॉकडाउन को अब खोलने का फैसला किया गया है. सोमवार से दिल्ली में सीमित अनलॉक किया जा रहा है. जिसमें बाजारों को खोलने की छूट नहीं दी गई है. हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले से अब व्यापारी फिर नाराज हो गए हैं.

अप्रैल के महीने में राजधानी में आए कोरोना के मामलों के बाद व्यापारी संगठनों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को नाकाफी बताया था और सरकार से दिल्ली में पूरा लॉकडाउन लगाने की मांग की थी. साथ ही राज्य सरकार के कोई फैसला न लेने पर स्वैच्छिक रूप से बाजारों को बंद करने की घोषणा कर दी थी. हालांकि कुछ दिन के भीतर की दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी थी. अब दिल्ली सरकार के पूरा अनलॉक न करने को लेकर व्यापारी एक बार फिर खफा हो गए हैं. इनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने अनलॉक तो किया है लेकिन बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडस ने शनिवार को की बैठक में सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है साथ ही यह भी कहा है कि व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.

हालांकि इस दिल्ली में अनलॉक और व्यापारियों के मसले पर एम्स के पूर्व निदेशक एमसी मिश्र कहते हैं कि अगर अभी बाजारों को न खोलने का फैसला किया गया है तो यह ठीक ही है. अगर प्रीमैच्योर स्टेज में लॉकडाउन को खोल दिया गया तो दिल्ली वापस उसी हालात में पहुंच जाएगी. वे कहते हैं कि व्यापारी पिछले महीने लॉकडाउन की मांग कर रहे थे, ऐसे में अभी भी समझना होगा कि जो कि कोरोना की जो स्थिति अब दिखाई दी है, लापरवाही की तो हालात खराब हो जाएंगे.अप्रैल में व्यापारियों ने सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए भेजी थीं चिट्ठियां

बता दें कि मध्य अप्रैल में दिल्ली सरकार की ओर से वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद व्यापारियों ने पत्र भेज-भेजकर सप्ताह के सातों दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की थी. 14 अप्रैल को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर कर्फ्यू को नाकाफी बताया था और पूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी साथ ही कहा था कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा.

इसके बाद 18 अप्रैल को कैट सहित तमाम व्यापारिक संगठनों ने 19 अप्रैल से दिल्ली के लगभग सभी बाजारों को बंद करने की घोषणा की. कैट की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि व्यापारियों ने चांदनी चौक सहित पेपर, इलेक्ट्रिक, ड्रग, इलेक्ट्रिोनिक्स,रेडियो, केमिकल, किराना, फुटवियर, साइकिल मार्केट आदि को खुद ही बंद करने का फैसला किया.

20 अप्रैल को दिल्ली के बड़े बाजारों जैसे चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, सदर, चावड़ी बाजार, लाजपत नगर, नई सड़क, खारी बावली, किनारी बाजार, कैमिकल मार्केट, ईस्ट दिल्ली, गांधी नगर, रबर, प्लास्टिक और कंप्यूटर मार्केट को बंद कर दिया गया. इस दौरान दिल्ली के प्रमुख बाजारों की एसोसिएशनों ने भी साथ दिया था. वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने और फिर उसे बढ़ाते रहने के दौरान व्यापारियों ने पुरजोर समर्थन किया और खुशी जाहिर की.

सुशील कुमार को एक और झटका, पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में हुई 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला की पुलिस रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी है। सुशील और अजय की छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज इन दोनों को अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े कई जरूरी पहलुओं की जांच के लिए और सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ चार दिन की ही रिमांड मंजूर की है। पुलिस ने कहा कि सुशील कुमार से और भी पूछताछ की जानी है। इस हत्याकांड में अब तक सुशील कुमार समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय बक्करवाला को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने 23 मई को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी चार मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार थे। पहलवान सुशील पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि अजय पर 50 हजार का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेशकर 12 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सिर्फ छह दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की थी। अदालत की कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि सुशील से पुलिस हिरासत पूछताछ यह जानने के लिए जरूरी है कि इस हत्याकांड के पीछे का पूरा षड्यंत्र और उद्देश्य क्या था। गौरतलब है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चार मई की रात दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के इलाके में पहलवान सुशील और उसके साथियों ने कथित तौर पर एक फ्लैट से सागर राणा और उसके दोस्तों का अपहरण कर लिया था और फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। इसमें सागर बुरी तरह घायल हो गया था और इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी। सुशील फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच छत्रसाल स्टेडियम में हुए विवाद से संबंधित मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने गत 18 मई को रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस को स्टेडियम का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा था। सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20-25 पहलवानों और असौदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर और दो अन्य को पीटता दिख रहा है। वीडियो में सभी लोग सागर को लात-घूंसों, डंडों, बैट व हॉकी से मारते दिख रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर व दो अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। सुशील देश के लिए लगातार दो ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिलवर मेडल जीता था। वह 2010 में विश्व चैंपियन भी रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2010, 2014 और 2018 में उन्होंने लगातार तीन गोल्ड मेडल जीते हैं।

संपादकीय

राष्ट्रीय कार्यबल को मिले अधिकार

सर्वोच्च अदालत ने पिछले हफ्ते एक राष्ट्रीय कार्यबल (नेशनल टास्क फोर्स- एनटीएफ) का गठन किया, जो एक सप्ताह के भीतर राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को चिकित्सकीय-ऑक्सीजन के आवंटन की नीति बताएगा, और अगले छह महीनों में एक राष्ट्रीय योजना की व्यापक रूपरेखा पेश करेगा, ताकि अभी और भविष्य में हम कोविड-19 से कारगर जंग लड़ सकें। विशेषज्ञों से भरा यह 12 सदस्यीय कार्यबल भरोसा जगाता है। हालांकि, इसका काम सिर्फ सिफारिश करना है, लिहाजा उसकी अनुशंसाओं पर फैसले लेने का अधिकार केंद्रीय नौकरशाही के पास ही होगा, जिसकी तस्वीर बहुत धवल नहीं है। लोग फैसले लेने वाली कोई पेशेवर और निष्पक्ष इकाई चाहते हैं, जिसके लिए कार्यबल ही उपयुक्त है, फिर चाहे वह मौजूदा स्वरूप में हो या फिर जरूरत के मुताबिक इसमें अन्य विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आवश्यक है कि वह इस राष्ट्रीय कार्यबल को इतना मजबूत करे कि वह कोविड-19 से जुड़े फैसले खुद ले सके। इस समय सबसे बड़ी जरूरत यही है कि राष्ट्रीय कार्यबल जैसी किसी इकाई द्वारा त्वरित निर्णय लिए जाएं। यह अभी सबसे बड़ी जरूरत है। एक उदाहरण से इसे समझिए। पिछले साल कोविड-19 के मामलों में उछाल आने के बाद मार्च में भारत सरकार के सचिवों के नेतृत्व में 11 अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया। फिर भी, प्रस्तावित 133 नए ऑक्सीजन-प्लांट में से सिर्फ 33 प्लांट स्थापित हो सके, और ये समितियां कुछ नहीं कर सकीं। नवंबर में, संसद की स्थाई समिति ने ऑक्सीजन-आपूर्ति, आईसीयू बेड और अन्य सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई थी। मगर जब बीते मार्च में दूसरी लहर ने भारत पर हमला किया, तब हम बिना तैयारी के थे। ऑक्सीजन-कोटे को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच की लड़ाई को ही लीजिए। आखिरकार अदालत ने दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित करने का फैसला दिया। क्षमता स्थापित करना और वितरण का निर्धारण करना भी मुद्दे हो सकते हैं। मगर, पिछले साल के अति-संतोष और इस बार की मौजूदा जरूरत में तुलना करें, तो यह साफ हो जाता है कि त्वरित अदालती फैसले और समितियों के आदेश क्या कर सकते हैं?

दूसरी बात, विशेषकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर निजी और स्थानीय स्तर पर सफलताएं देखी गई हैं। केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य न सिर्फ अपने यहां ऑक्सीजन-रिजर्व को बनाए रखने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने अन्य सूबों की भी मदद की। नंदुरबार (महाराष्ट्र) के युवा जिलाधिकारी ने अपने जिले में तीन ऑक्सीजन-प्लांट लगाए, तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त को भी अपने कामों के लिए भरपूर सराहना मिली। मगर इस तरह के निजी प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं, और एक केंद्रीय इकाई की जरूरत होती ही है, जो रोजाना के आधार पर चुनौतियों को देखते हुए फैसले ले। जैसे, ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके आवंटन को लेकर अगला पखवाड़ा काफी अहम है, इसलिए राष्ट्रीय कार्यबल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैठकें करने और नीतियों पर विचार-विमर्श के बजाय रोजाना के आधार पर काम करे। भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में एक समिति पहले से ही ऑक्सीजन-आवंटन पर काम कर रही है। सचिव चाहें, तो प्रतिदिन की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यबल को दे सकते हैं और वहां से आदेश ले सकते हैं। इससे राज्य भी संतुष्ट होंगे और केंद्र पर उंगली उठाने के बजाय वे अपने कामकाज पर ध्यान देंगे। तीसरी बात, विशेषज्ञ पैनल भारत की वैक्सीन-नीति को तैयार करने में (याद रखें, यह मामला भी इस समय अदालत के अधीन है) भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। टीके को लेकर संघीय संबंधों में तनातनी को देखते हुए टीकों के वितरण का फैसला राष्ट्रीय कार्यबल को सौंपा जाना चाहिए। व्यवस्थित टीकाकरण के लिए, रोग की मौजूदा व कथित गंभीरता को देखते हुए विभिन्न जनसांख्यिकी खंडों के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रणनीति के आधार पर काम करने की दरकार है। चौथी बात, कोविड-19 प्रोटोकॉल पर काफी ज्यादा भ्रम होने की वजह से राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सा संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ डॉक्टरों व विशेषज्ञों के बयान हैं कि नागरिकों को रेमडेसीवर, टोसिलीजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहना चाहिए और खास परिस्थितियों में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ, होम आइसोलेशन में डॉक्टर धड़ाधड़ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यबल को इस पर तत्काल गौर करना चाहिए और एक 'नेशनल एडवाइजरी' जारी करनी चाहिए। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कार्यबल जनता से जीनोम-सीक्वेंसिंग की स्थिति और नए वेरिएंट को लेकर सूचनाएं भी साझा कर सकता है। पांचवीं बात, मदद के रूप में विदेश से चिकित्सा सामान की आपूर्ति लगातार हो रही है और भारत सरकार की समिति मानदंडों के अनुसार इनके वितरण का काम देख रही है। ऐसा न हो कि आवंटन में देरी और पूर्वाग्रह के कारण कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। दैनिक आधार पर समिति को सुनने के बाद राष्ट्रीय कार्यबल को वितरण का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगले छह महीनों के लिए कोविड-19 से संबंधित फैसले राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा ही लिए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण लंबित मामलों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता इसके पास है और इसकी छवि भी निष्पक्ष है। कई समितियां पहले से ही राष्ट्रीय कार्यबल की मदद करने के लिए मौजूद हैं। मौजूदा आभासी दौर में एक दिन में दो छोटी-छोटी बैठकों में ही सभी जरूरी मसलों पर फैसला हो सकता है। आलोचक राष्ट्रीय कार्यबल को न्यायिक अतिरेक की मिसाल के रूप में पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इससे चुनी गई सरकार के सांविधानिक अधिकारों का हनन होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सशक्त निकायों की स्थापना की है, जैसे, दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा किया गया था। लिहाजा, विपत्ति के समय असाधारण उपाय अपनाना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ केंद्र और राज्यों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करेगा, बल्कि उनके प्रयासों की सराहना भी करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यबल निष्पक्ष और पेशेवर फैसले लेने के लिए सरकारी आंकड़ों और संसाधनों पर ही काफी हद तक निर्भर रहेगा।

प्रवीण कुमार सिंह

कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाएं और बेवजह न करें सरकार की आलोचना

देश के कई शहरों में अस्पताल इंटरनेट मीडिया पर हर दिन आग्रह कर रहे हैं आक्सीजन सप्लाई को नियमित किया जाए, क्योंकि अनियमित सप्लाई से त्रासदीपूर्ण मौतें हो रही हैं। इन मौतों की जवाबदेही किसकी है? पिछले कुछ सप्ताह के दौरान इतना तो स्पष्ट हो गया है कि केंद्र व राज्यों ने कोविड की दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, शायद उनकी प्राथमिकताएं कहीं और थीं। स्थिति बद से बदतर इसलिए भी हो रही है, क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच ही नहीं राज्यों के अपने जिलों में भी समन्वय का अभाव है।

कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी से जूझ रहे भारत ने हैजा, चेचक, प्लेग और पोलियो जैसी महामारियों को भी झेला है। अगर बात बिल्कुल हाल के दौर की करें तो डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप भी अच्छा-खासा रहा। दोनों ही मच्छर जनित रोग थे और देश के विभिन्न हिस्सों में गंदे पानी के ठहराव ने इन मच्छरों के लिए प्रजनन आधार प्रदान किया। इन्होंने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया था। इन प्रकोपों के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए और राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक मरीज सामने आए थे। अब बात कर लें ओडिशा में 2014 में पीलिया के प्रकोप की। इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया, जो इस बीमारी का कारण बना था। इसी दौरान स्वाइन फ्लू के प्रकोप से भी देश को सामना करना पड़ा। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा वायरस ही है। इससे 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से थे। मार्च 2015 तक कई सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के बाद भी देश भर में लगभग 33 हजार मामले सामने आए और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहने का भाव यह है कि महामारियों से हमारा संपर्क हर काल में होता ही रहा है, पर लोग दुख देने वाली स्मृतियों को भूल जाना चाहते हैं। जिंदगी खुशियां मनाने के लिए है न कि दुख की घड़ियों को याद रखने के लिए। क्या देश मच्छरों के काटने के कारण 2017 में गोरखपुर शहर में सैकड़ों बच्चों की मौत को भूल सकता है? इस वायरल संक्रमण से मस्तिष्क की सूजन होती है, जिसके चलते शारीरिक विकलांगता होती है और कुछ मामलों में रोगी की जान चली जाती है।

आज दुनिया और भारत कोविड महामारी को झेल रहा है। यह 2019 में चीन से शुरू हुई थी। इसके संक्रमण के संकेतों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। कोरोना को शिकस्त तो देनी ही होगी। भारत में कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक टीके की लगभग 18 करोड़ लोगों को खुराक दी जा चुकी है। भारत ने कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए दो तरह के टीका भी ईजाद कर

लिया। तीसरे टीके स्पुतनिक का आयात किया है। जल्द ही कुछ और टीके आने वाले हैं। टीके के मामले में भारत के विज्ञानी विश्व भर के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। हमारे देश में बनी वैक्सीन दुनिया के कई देशों में जा रही है। इसके चलते दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने वाली वैक्सीन ईजाद करके भारत ने सिद्ध कर दिया है कि मानव जाति की सेवा के लिए वह सदैव प्रतिबद्ध है। इस वैक्सीन को लेकर शुरू में कुछ आशंकाएं और संदेह भी जाहिर किए जा रहे थे। उन्हें दूर करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री आगे आए। यह सामान्य बात नहीं।

कोरोना वायरस ने दुनिया के हरेक इंसान की आंखों से आंसू निकलवा दिए। पृथ्वी पर मौजूद हरेक धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि से संबंधित मनुष्य की ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए, ताकि दुनिया फिर से अपनी गति से चलने लगे। कोरोना वायरस को लेकर कहीं भी टीका ईजाद होता है तो मानव जाति के लिए राहत की बात होती, पर हरेक भारतीय आज इस बात पर गर्व कर सकता है कि भारत में भी एक प्रभावी कोरोना वायरस का टीका ईजाद कर लिया गया।

मनुष्य की जिजीविषा के सामने कोई भी महामारी टिक नहीं सकती। इसलिए ही तो मानव तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ता रहा है। अब कोरोना का भी नाश होगा। दुनिया फिर से पहले की तरह अपनी गति से चलेगी, पर यह तब ही संभव है जब सभी पात्र लोग कोरोना से बचने के लिए टीका लगवा लें और बेवजह सरकार और उनके प्रशासन की आलोचना न करें।

कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी प्रशासनिक नाकामी का मुखर साक्ष्य- भारत हमेशा से ही आक्सीजन के प्रमुख निर्यातकों में रहा है, इसलिए कोरोना संक्रमण की भयंकर दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी की जो निरंतर खबरें आ रही हैं, वह भारत की प्रशासनिक नाकामी का सबसे मुखर साक्ष्य है। हालांकि राज्य सरकारें कह रही हैं कि वे मौतों के असल कारण की जांच कर रही हैं, लेकिन इस बात में कोई शक ही नहीं है कि आक्सीजन संकट वास्तविक में है। आक्सीजन की कमी मुख्यत- प्रशासनिक कारणों से है कि मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं है और कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इस पर भी सियासी झुकाव के अनुसार राजनीति हो रही है।

दरअसल किसी संकट का समाधान तभी किया जा सकता है जब पहले यह स्वीकार कर लिया जाए कि वाकई में संकट है, शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर घुसा देने से तूफान से कहां बचा जाता है? जब सभी विशेषज्ञों की राय यह थी कि कोविड-19 की दूसरी लहर मार्च-अप्रैल 2021 में आएगी जो पहली लहर से अधिक घातक होगी और उसमें आक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आक्सीजन निर्यात का दोगुना किया जाना भी प्रशासनिक चूक ही है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत ने 9,300 मीट्रिक टन से अधिक आक्सीजन का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2020 में भारत ने 4,500 मीट्रिक टन आक्सीजन का निर्यात किया था। जनवरी 2020 में भारत 352 मीट्रिक टन आक्सीजन निर्यात कर रहा था, जिसमें जनवरी 2021 में 734 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत ने दिसंबर 2020 में 2,193 मीट्रिक टन आक्सीजन निर्यात किया था, जबकि दिसंबर 2019 में निर्यात की मात्रा 538 मीट्रिक टन थी। सरकार का कहना है कि महामारी वर्ष 2020-21 में सिर्फ औद्योगिक आक्सीजन ही निर्यात किया गया था न कि मेडिकल आक्सीजन। लेकिन तथ्य यह है कि अब जब अधिक सांसें उखड़ रही हैं, आक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है और अनेक राज्य इसकी कमी की शिकायत कर रहे हैं, तो अस्पतालों की तरफ औद्योगिक आक्सीजन ही भेजी जा रही है। बहरहाल, आक्सीजन संकट उस समय स्पष्ट हो गया जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया।

एक राज्य की आक्सीजन जरूरत निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि मांग केस लोड पर निर्भर करती है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार आक्सीजन की व्यवस्था करे, विशेषकर जब सोलिसिटर जनरल का दावा है कि देश के लिए पर्याप्त आक्सीजन सप्लाई है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी कमी है। इस पर अलग से बहस की जा सकती है कि आक्सीजन का असंतुलित वितरण है या वास्तव में विकट कमी है, पर चिंता का विषय यह है कि नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और सरकारें अपने नौकरशाहों के जरिये आपस में टकरा रही हैं एक-दूसरे को अक्षम साबित करने के लिए। देश के कई शहरों में अस्पताल इंटरनेट मीडिया पर हर दिन आग्रह कर रहे हैं आक्सीजन सप्लाई को नियमित किया जाए, क्योंकि अनियमित सप्लाई से त्रासदीपूर्ण मौतें हो रही हैं। इन मौतों की जवाबदेही किसकी है? पिछले कुछ सप्ताह के दौरान इतना तो स्पष्ट हो गया है कि केंद्र व राज्यों ने कोविड की दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, शायद उनकी प्राथमिकताएं कहीं और थीं। स्थिति बद से बदतर इसलिए भी हो रही है, क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच ही नहीं राज्यों के अपने जिलों में भी समन्वय का अभाव है।

भविष्य में जैविक युद्ध की बढ़ती आशंका से निपटने के लिए करनी होगी बड़ी तैयारी

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी आशंका जता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है क्या भारत किसी जैविक युद्ध का शिकार तो नहीं हुआ है जिसने अचानक चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त करके इतनी बड़ी तबाही मचा दी हो। कोरोना वायरस कैसे और कहां से आया इसको लेकर कई तरह की बातें पिछले एक साल से की जा रही हैं, लेकिन हाल में ही इससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

चीन के विज्ञानियों ने कोविड-19 महामारी से पांच साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है।

चीनी विज्ञानियों ने सार्स कोरोना वायरस का 'जैविक हथियार के नए युग' के तौर पर उल्लेख किया था, कोविड जिसका एक उदाहरण है। दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि चीन में वर्ष 2003 में फैला सार्स एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता है, जिसे आतंकियों ने जानबूझकर फैलाया हो। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ताकि दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्था और चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त कर सके। चीन, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को काबू में करना चाहता था इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना जरूरी था। वास्तव में ट्रंप चीन की तेज रफ्तार में कांटा बनकर खड़े थे। चीन ने इस वायरस का केंद्र बिंदु वुहान में ही रखा जहां दुनिया भर के लोग काम करते हैं। चीन के अन्य शहरों में इसका असर बहुत कम देखा गया। लेकिन अन्य देशों में इसने देखते ही देखते तबाही मचा दी।

दरअसल वुहान में जब हालात बिगड़ने लगे या कहें कि बिगाड़े गए, तो दूसरे देशों के लोग अपने देश को भागने पर मजबूर हो गए। भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। इसके साथ चाइनीज वायरस भी एयरलिफ्ट हुआ और बडी संख्या में लोगों को संक्रमित करने लगा। दूसरी लहर के प्रति भारत की ही तरह अमेरिका ने भी पहली लहर में इसे हल्के में लिया और चीन की योजना बिना किसी परिश्रम के सफल हो गई। दूसरी ओर इसके फैलने के तुरंत बाद चीन की वैक्सीन बाजार में आ गई। पूरा विश्व हैरान रह गया कि अभी तो वायरस का विश्लेषण भी आरंभ नहीं हुआ था, विज्ञानी वैक्सीन पर रिसर्च ही कर रहे थे और चीन ने वैक्सीन बेचना भी शुरू कर दिया।

गौरतलब है कि चीन ने सबसे पहले वुहान में लॉकडाउन लगाया था, तो अमेरिका हैरान था कि चीन को यह कैसे पता कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो सकता है। उसी लॉकडाउन में चीन ने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा दी थी और कुछ ही महीनों में पूरे चीन में टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो गया। चीन ने अपने लोगों में पहले ही टीका लगा कर बचाव भी कर लिया और दुनिया भर में अपना सामान भी बेच लिया। इस बीच भारत और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश स्वयं को इसके शिकंजे से बचाने के लिए पूरे प्रयास में जुटे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि चीन अपने वायरस को निरंतर अपडेट कर रहा है और अपने दुश्मन देशों को हेल्थ सिस्टम में उलझाकर रखना चाहता है। पूरी आशंका है कि नए वैरिएंट अपडेट वायरस ही हो सकते हैं। अब तक के तमाम तथ्य इस बात को ही इंगित करते हैं कि इस समस्या की असली जड़ चीन ही है। ऐसे में पूरी विश्व बिरादरी को चीन के विरुद्ध एकजुट होना होगा। साथ ही, भविष्य में जैविक हथियारों या किसी भी तरह के जैविक युद्ध से निपटने के लिए भी बड़ी तैयारी करनी होगी।

तूफान और तैयारियां

पिछले सप्ताह तौकते की तबाही झेलने के बाद अब देश एक अन्य चक्रवाती तूफान यास का सामना कर रहा है। तौकते का सबसे तीखा असर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला था, यास का ज्यादा प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में है। हालांकि तूफान के नुकसानों का ब्योरा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि यास कमजोर पड़ रहा है और तत्काल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि तूफान की शक्ति और इसके प्रभाव क्षेत्र की जानकारी मिल जाने की वजह से जरूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं।

जानकार बताते हैं कि कम से कम तूफान के मामले में हमारी तैयारियां धीरे-धीरे बेहतर होती जा रही हैं। हर तूफान के अनुभव का फायदा अगले तूफान से बचाव की तैयारियों में होता है। इस बार भी समय रहते तटवर्ती इलाकों के कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। पश्चिम बंगाल ही नहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई थीं। यहां तक कि झारखंड में भी टीम भेजने की तैयारी थी क्योंकि मिली सूचनाओं के मुताबिक ऐसी संभावना थी कि जमशेदपुर और रांची में भी तूफान का असर हो सकता है। हालांकि तमाम तैयारियों के बावजूद ऐसे तूफान नुकसान तो पहुंचाते ही हैं।

एक नुकसान उस स्तर पर होता है, जिससे बचाव की तैयारी संभव ही नहीं। खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान या आबादी वाले हिस्सों में पानी भरने से होने वाले नुकसान इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ऐसे भी नुकसान हैं, जो हमारी तैयारी या सावधानी में कमी का परिणाम होते हैं। उन नुकसानों का पहले से अंदाजा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, तूफान में नावों या जहाजों के फंसने से होने वाली मौतें टालने के बहुत सारे इंतजाम हैं। मछुआरों को पहले से आगाह कर दिया जाता है। इस बार भी तटरक्षक दलों की सावधानी से बंगाल की खाड़ी में गईं सभी 265 नावें किनारे लौट आई थीं।

इसी तरह की कवायद तौकते के दौरान भी की गई थी। बावजूद इसके, ओएनजीसी के एक प्रॉजेक्ट में लगा बार्ज पी 305 तूफान में फंस कर डूब गया, जिससे 70 से ज्यादा लोग मारे गए। यह लापरवाही का मामला था। तूफान की सूचना होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बार्ज को समय रहते किनारों की ओर लाने का फैसला नहीं किया गया, जिसकी कीमत इतनी सारी बेकसूर जिंदगियों के रूप में चुकानी पड़ी। बहरहाल, इस मामले में तो जिम्मेदारी तय कर लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों को उपयुक्त सजा मिलनी ही चाहिए।

पर्यावरण की पर्याप्त रक्षा करके ही धरती पर मानव अस्तित्व को रख सकते है कायम

इसी प्रकार मानव स्वास्थ्य एवं वायरसों पर शोध व परीक्षण कर रहे एक अमेरिकी शोधकर्ता का ताजा निष्कर्ष है कि इन वायरसों का मुख्य वाहक दूषित पर्यावरण है और मानव जाति की सुरक्षा के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अभी इसके कहर से निजात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि न तो पूर्ण रूप से इसकी प्रकृति, गुण, किस्मों तथा विशेषताओं का पता चल पाया है और न ही इसका वास्तविक टीका बन पाया है।

कोरोना से ठीक होने के बावजूद आम जनता की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और नए रूपों में आकर कोरोना सबको हैरान कर रहा है। ताजा मामला ब्लैक फंगस का है जो कोरोना से ठीक होने वालों को बेहद तेजी से अपनी चपेट में लेकर आंखें, जबड़े आदि को अपने चपेट में ले रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर देश भर में इसके सौ से अधिक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। विज्ञानी इसके पीछे भी कोरोना के साइड इफेक्ट मान रहे हैं। तमाम वैक्सीनों, दावों, संभावनाओं व उम्मीदों को धता बताते हुए खतरनाक वायरस कोरोना ने एक बार फिर से मानवता पर नए रूप में धावा बोला है। इसने वैक्सीन के असर को भी काफी हद तक कम कर दिया है।

आज अनेक लोग न केवल बड़ी संख्या में इस अबूझ वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी जान से महरूम भी हो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि डेढ़ साल बाद भी अत्याधुनिक व अति उन्नत कही जाने वाली वर्तमान मानव जाति इस मामूली से रहस्यमय वायरस के आगे नतमस्तक है। इस बार खास बात यह है कि पहले जहां यह बेहद कम तापमान पर सक्रिय हुआ था, वहीं इस बार यह औसतन 40 डिग्री के तापमान पर अवतरित हुआ है। यानी तापमान वाली पहली थ्योरी गलत साबित हुई है। इस बार इससे न केवल विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि मृत्यु दर भी पहले के मुकाबले बहुत अधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को संदेह है कि यह नया वायरस खतरनाक रूप धारण कर सकता है।

भारत समेत समस्त देशों की सरकारों की पूर्ण मुस्तैदी, सजगता व युद्ध स्तरीय प्रयासों के बावजूद मामला दिनोंदिन भयावह होता जा रहा है। इससे बचने की हरसंभव कोशिशें व उपाय निष्फल हो रहे हैं। ऐसे में मानव जाति के पास अपने आप को अलग थलग कर लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। संपूर्ण विश्व में इस समय इस पर निरंतर शोध व परीक्षण हो रहे हैं और हर नए शोध में नया नया निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। पहले गर्म पानी पीने व लगभग 40 डिग्री तापमान वाले कमरों में रहना इसका उपचार बताया जा रहा था, पर अमेरिका के न्यूजर्सी में यह परीक्षण भी निष्फल रहा।

अमेरिकी यूनिवर्सिटी मैरिलैंड का ताजा शोध है कि इसके प्रसार के लिए दूषित खान-पान, छुआछुत, श्वास प्रक्रिया व हमारा वायुमंडल यानी तेज हवाएं जिम्मेदार हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के कृत्रिम वातावरण बनाकर जानवरों पर गहन परीक्षण जारी हैं। प्लेग के बाद यह पहली ऐसी महामारी है जिसे लाइलाज माना जा रहा है। आम जनता में घबराहट न फैले इस कारण वैश्विक स्तर पर तो लगभग सभी देशों के अधिकारिक आंकड़ों में इससे प्रभावित तथा मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ताजा अनुमान है कि इससे प्रभावितों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। दुनियाभर में इस बीमारी के प्रति जागरूकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं के नवीन मतानुसार ये वायरस अब हर प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में बहुत तेजी से पनप रहे हैं और फिर मानव जाति में अपना प्रसार करते चले जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में सभी संभव सुरक्षात्मक उपायों, लॉकडाउन, तापमान नियंत्रण आदि के बावजूद संक्रमण के मामलों में चिंतनीय तेजी जारी है। ये वायरस मूलत- पर्यावरण में उत्पन्न होकर मानव शरीर में अपना प्रसार करते हैं। इसके अलावा, अशुद्ध अथवा संक्रमित मांस खाने से भी यह मानव शरीर में पहुंचता है। शोध अध्ययन बताते हैं कि डेंगू, स्वाइन फ्लू व कोरोना जैसे सभी खतरनाक जानलेवा वायरस मूलत- जानवरों से ही आए हैं। रूस में चल रहे परीक्षणों के मुताबिक लगभग 74 डिग्री तापमान वाले नाले के पानी में इस वायरस का प्रसार बहुत तीव्र पाया गया और इसी तापमान पर बिल्कुल स्वच्छ पानी में अपेक्षाकृत कम।

इसी प्रकार मानव स्वास्थ्य एवं वायरसों पर शोध व परीक्षण कर रहे एक अमेरिकी शोधकर्ता का ताजा निष्कर्ष है कि इन वायरसों का मुख्य वाहक दूषित पर्यावरण है और मानव जाति की सुरक्षा के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अभी इसके कहर से निजात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि न तो पूर्ण रूप से इसकी प्रकृति, गुण, किस्मों तथा विशेषताओं का पता चल पाया है और न ही इसका वास्तविक टीका बन पाया है।

आधुनिक युग की यह सबसे उन्नत मानी जाने वाली मानव सभ्यता को अपने हर संभव पैमाने, वातावरण, परिवेश तथा परीक्षण में यह वायरस पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत व बहुरंगी रूप में विद्यमान मिलता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इससे बचाव हेतु जरूरी सावधानी बरती जाए। पर्यावरण की पर्याप्त रक्षा करके ही धरती पर मानव अस्तित्व को कायम रखा जा सकता है।

इसके लिए अलग अलग प्रकार के कृत्रिम वातावरण बनाकर जानवरों पर गहन परीक्षण जारी हैं। प्लेग के बाद यह पहली ऐसी महामारी है जिसे लाइलाज माना जा रहा है। आम जनता में घबराहट न फैले इस कारण वैश्विक स्तर पर तो लगभग सभी देशों के अधिकारिक आंकड़ों में इससे प्रभावित तथा मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ताजा अनुमान है कि इससे प्रभावितों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। दुनियाभर में इस बीमारी के प्रति जागरूकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा निरस्त, जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटर की परीक्षा कराने की योजना

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संमक्रण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में परिस्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने की योजना भी बनाई है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मंथन के बाद 2021 की हाईस्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की कक्षा दस की परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही सरकार ने कक्षा-12 की परीक्षा को कराने की योजना भी बना ली है। प्रदेश के माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के कहर के कारण आगे की परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की कक्षा 12 की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए हमने योजना तैयार की है और जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इसका आयोजन भी प्रस्तावित है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा अवधि को डेढ़ घंटा रखा जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को मात्र तीन प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।

हाईस्कूल की परीक्षा निरस्त, प्रोन्नत होंगे सभी छात्र-छात्राएं॑ डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली हुई महामारी के कारण उत्पन्न इस असाधारण परिस्थितियां में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में व्यापक छात्र हित तथा जनहित में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2021 की कक्षा10 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 29,94,312 बच्चों को बड़े संकट में फंसने से मुक्ति मिलेगी। कक्षा 10 के बच्चों के कक्षा 11 में प्रोन्नति के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश भी उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया है।

कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी॑ डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व तथा छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के कारण ही सभी सभी सावधानियों को बरतते हुए तथा कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुकूल परिस्थितियों के रहते हुए 2021 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराने की प्रदेश सरकार ने योजना भी बना ली है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगा। पूर्व के भांति इस वर्ष भी 15 कार्य दिवसों में परीक्षा संपादित की जाएगी। छात्रों के हित में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नपत्र की अवधि को मात्र डेढ़ घंटे रखा जाएगा तथा छात्रों को प्रश्नपत्र के किन्ही दस में से सिर्फ तीन का ही उत्तर देना होगा। बच्चों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को लगातार सैनिटाइज भी किया जाएगा।उत्तर

प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है।

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि॑ उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण निर्णय की शनिवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसके साथ ही सरकार उनके पठन-पाठन की भी व्यवस्था कर रही है। हमने बेसिक के साथ ही अन्य क्लास के भी बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम किया है। सरकार अब हाईस्कूल के 29,94312 बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नत करने की प्रक्रिया में लगी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस बड़े अभियान में लगे हैं। इसके साथ ही हम लोग इंटर के 26,30,216 छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उनकी परीक्षा कराने पर तैयार हैं। इनको आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विधा का चयन करना होगा, इसी कारण इनकी परीक्षा जरूरी है। हम परीक्षा में भी इनको पांच के स्थान पर तीन ही प्रश्न करने के लिए देंगे। परीक्षा का समय भी मात्र डेढ़ घंटा का ही होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन होगा और शारीरिक दूरी का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा।

छात्र-छात्राओं के हित में निरंतर काम॑ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, निरंतर छात्र-छात्राओं हित में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने 2020 के जुलाई माह में ही करोना महामारी के दृष्टिगत पठन-पाठन में हो रहे व्यवधान से पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी कर दी थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष के लॉकडाउन से ही ऑनलाइन शिक्षण के साथ-साथ दूरदर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ई-विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल तथा यूट्यूब पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई-ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से बच्चों का पठन-पाठन सुनिश्चित किया। इसके साथ ही 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्रों के बनाए। जिससे प्रदेश में पठन-पाठन का माहौल बना रहा।

प्रोन्नत होंगे कक्षा छह से 11 तक के सभी छात्र-छात्राएं॑ सरकार ने इसके साथ ही समस्त बोर्ड के सभी स्कूलों के कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 के छात्रों को भी प्रोन्नत करने का भी निर्णय कर लिया है। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 6, 7 ,8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय का शासनादेश पूर्व में जारी कर दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए। कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे। यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए। यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 की उक्त वर्णित व्यवस्था, प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। इन सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी विद्यालय ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो अभिभावक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक समिति के समक्ष शिकायत करने को स्वतंत्र हैं।

संक्षिप्त खबर

अब यूपी में 50 हजार से कम कोरोना के एक्टिव केस, 2,287 नए संक्रमित मिले

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। शनिवार को प्रदेश में 61 जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना के 50 से कम मरीज पाए गए। इसमें 18 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम मरीज मिले हैं। सिर्फ चार जिले लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में 100 से अधिक रोगी मिले। 49 दिनों बाद सक्रिय केस भी घटकर 50 हजार से नीचे पहुंच गए हैं। अब 46,201 मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 2,287 नए रोगी मिले हैं, जबकि 157 लोगों की और मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 3,30,289 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 4.87 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। अब पाजिटिविटी रेट घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया है। अब तक प्रदेश में कोरोना से कुल 16.88 लाख लो ग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 16.21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट बढ़कर 96.1 फीसद हो गया है।

अब तक कुल 20,208 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। 12 वर्ष से कम बच्चा तभी जाएं अभिभावक स्पेशल केंद्र पर ॑एक जून से प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होगा। छोटे जिलों में दो-दो और बड़े जिलों में चार-चार अभिभावक स्पेशल टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं लोग जिनका कम से कम एक बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है, वह ही अभिभावक स्पेशल टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने के लिए स्लाट बुक करें। उन्हें मौके पर बच्चे का आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर उनके पास प्रमाण नहीं है तो उन्हें टीकाकरण केंद्र से वापस कर दिया जाएगा।

बिहार में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने पर मांझी और सहनी एकमत, साथ आवाज उठा सरकार पर बढ़ाया दबाव

पटना । बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जारी संशय के बीच अब सरकार के सहयोगी चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। इस मामले को लेकर शनिवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी से मुलाकात भी की। राज्य इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। जिस वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। चुनाव होंगे या नहीं इसे लेकर फिलहाल अनिर्णय की स्थिति है। अनिश्चितता की इसी स्थिति के बीच मुकेश सहनी शनिवार को हम प्रमुख जीतन राम मांझी के आवास जा पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने कोरोना के साथ पंचायत चुनाव को लेकर लंबी बातचीत की।

दानिश ने कहा- महीने में दो-चार बार मिलते रहते हैं दोनों नेता- बैठक के बाद हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान में कहा कि मांझी और सहनी के बीच औपचारिक मुलाकात हुई है। सहनी मांझी को अपना अभिभावक मानते हैं। दोनों की महीने में दो चार बार मुलाकात होती रहती है। उन्होंने कहा कि मांझी और सहनी दोनों चाहते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल कम से कम छह महीने के लिए बढ़ाया जाए।

चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक बढ़ाया जाए कार्यकाल- मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने ट्वीट कर कहा डिजिटल सिग्नेचर के वजह से पंचायत में कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यदि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया तो विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक के लिए बढ़ाना चाहिए।

भाजपा के कई नेता भी कर चुके हैं ऐसी ही मांग- बिहार भाजपा के कई नेता भी राज्य में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। भाजपा के एमएलसी रजनीश कुमार ने सरकार से आग्रह किया है कि चुनाव संपन्न होने तक मौजूदा जनप्रतिनिधियों को ही काम करने का मौका दिया जाए।

झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 788 लोग पकड़े गए, 5.52 लाख रुपये का जुर्माना

रांची । स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व बिना मास्क वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य में

29 मई को भी पुलिस ने अपने 931 चेक प्वाइंट पर चेकिंग लगाया था। इस दरम्यान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 788 लोग पकड़े गए। इनसे पुलिस ने तीन लाख 38 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला। पुलिस ने बिना मास्क वाले 3095 लोगों को भी पकड़ा, जिनसे दो लाख 13 हजार 400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यानी लॉकडाउन उल्लंघन व बिना मास्क वालों से पुलिस ने पांच लाख 52 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला है। खूंटी व गढ़वा जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एक-एक प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। राजधानी रांची में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 183 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पकड़ा। इसी तरह बिना मास्क में भी सात लोग पकड़े गए। दोनों ही मामले में पुलिस ने 95000 रुपये का जुर्माना वसूला है। राज्य में कोरोना का संक्रमण कम होने से अब गिने-चुने जिले में ही 50 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। यहां लगातार तीन दिनों से एक हजार से कम संख्या में नए संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं, लगातार दो दिनों से सभी जिलों में सौ से कम संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। कई जिलों में तो दस से भी कम संख्या में नए संक्रमित मिल रहे हैं। शनिवार को शाम तक जिन जिलों की जांच रिपोर्ट आ चुकी थी, जिनमें सरायकेला खरसावां को छोड़कर सभी जिलों में 50 से कम संख्या में संक्रमित मिले थे। सरायकेला खरसावां में 56, जामताड़ा में 41, पश्चिमी सिंहभूम में 28, रामगढ़ में 24, पलामू में 23, साहिबगंज में छह, गढ़वा में पांच नए संक्रमित मिले। वहीं, रामगढ़ में 66, पलामू में 62, पश्चिमी सिंहभूम में 54, सरायकेला खरसावां में 43, गढ़वा में 36, जामताड़ा में 16 मरीज स्वस्थ भी हुए। इन जिलों में सिर्फ रामगढ़ में एक मरीज की मौत की सूचना है।

उत्तर प्रदेश में एक तारीख से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत, खुलेंगे बाजार

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण में सेकेंड स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के कारण एक मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में एक जून से आंशिक ढील दी जाएगी। इस दौरान अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा। इसमें रात आठ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। ऐसे में सरकार ने अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर टीम की बैठक में इस पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि अभी इस पर मंथन चल रहा है कि पहले किन-किन गतिविधियों को शुरू किया जाए। साथ ही बाजारों को एक साथ खोलने की बजाय इस तरह खोलने की योजना है कि एकदम से भीड़ न हो। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। इस संबंध में सम्भवतः रविवार को गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा की और इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में ढील देने पर सहमति बनी। प्रदेश में एक जून से उद्योग, दुकान तथा बाजारों को राहत दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में अभी राहत नहीं दी जाएगी, जबकि नाइट कर्फ्यू हर जिले में जारी रहेगा। मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में चर्चा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक कर पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। सरकार फेस वाइस अनलॉक करेगी। प्राथमिकता के आधार पर छूट दी जाएगी। धीरे-धीरे इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा।

कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू इस बार भी चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। प्रदेश में अब 24 घंटे में दो हजार तक नए संक्रमित आने से इसका प्रभाव कुछ कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद अब सरकार जनता को राहत देने के मूड में है। प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 22 से घटकर एक प्रतिशत रह गई है।

कोविड-19 के कारण माता-पिता को गंवा देने वालों बच्चों की पालनहार बनी योगी आदित्यनाथ सरकार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को गंवा देने वाले निराश्रित बच्चों का सहारा योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इन बच्चों को बाल सेवा योजना के अंतर्गत इनके बालिग होने तक योगी आदित्यनाथ सरकार सारा खर्च उठाएगी।

कोरोना वायरस संक्रमण की विभीषिका के कारण प्रदेश में कई बच्चों के माता-पिता का असमय देहान्त हो गया है। ऐसे बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को गंवा देने वाले निराश्रित बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शनिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ ही विवाह का खर्च सरकार देगी। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार लैपटॉप व टेबलेट भी देगी।

कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ले ली है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार केयरटेकर को अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपया प्रतिमाह देगी। जिन

बच्चों ने दस वर्ष की कम उम्र में ही अपने मां-बाप को खो दिया है, उनको राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। अवयस्क बच्चियों की देखभाल के साथ और पढ़ाई के लिए उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रखा जाएगा।

राज्य सरकार की अभिनव पहल के बारे में औपचारिक घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित थे, तो उन्हें अथवा विधिक अभिभावक को खो दिया हो और जो अनाथ हो गए हों तो राज्य सरकार द्वारा उनकी समुचित देखभाल की जाएगी। ऐसे बच्चों को जीवन में उन्नति के सभी अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए राज्य सरकार सभी जरूरी प्रबन्ध करने के लिए तत्पर है। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की जा रही है।

इसके साथ ही 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी उनकी देखभाल की जाएगी। यूपी सरकार अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपया भी देगी। इसके साथ ही स्कूल में पढने वाले और व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले बच्चों को टेबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण काल में अनाथ 555॑ कोरोना संक्रमण काल मेंअनाथ हुए 555 बच्चों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है। सभी जिलों के डीएम से भी रिपोर्ट मांगी गई है। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने बताया की सभी जनपदों के डीएम को ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार कर भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी बच्चों के संबंध में सूचनाएं संबंधित विभागों, जिला प्रशासन को पूर्व से प्राप्त सूचनाओं, चाइल्ड लाइन, विशेष किशोर पुलिस इकाई, गैर सरकारी संगठनों, ब्लॉक तथा ग्राम बाल संरक्षण समितियों, कोविड रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित निगरानी समितियों और अन्य बाल संरक्षण हितधारकों के सहयोग व समन्वय किया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एलान किया है कि कोरोना की वजह से जिन बच्चो के दोनों पैरेंट्स की मौत हो गई है या फिर अभिभावक की मौत हो गई है, उनकी पीएम केयर्स फंड से मदद की जाएगी। 18 वर्ष का होने के बाद ऐसे बच्चों को मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और 23 वर्ष का होने पर 10 लाख दिए जाएंगे।

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत नाजुक, मेदांता में अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत नाजुक हो गई है। रामपुर से सांसद आजम खां का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।

मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 72 वर्षीय आजम खां को बीती नौ मई के लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों उनको आइसीयू से भी बाहर प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को फेफड़ों में संक्रमण बढने के कारण उनको फिर आइसीयू में शिफ्ट किया गया था। शनिवार सुबह हालत गंभीर होने पर आजम खां को फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाया गया है।

आजम खां ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उनको फेफड़ों में फाइब्रेसिस की समस?या हो गई थी, इस वजह से आजम खान को लगातार सांस लेने में दिक?कत हो रही है। बीच में उनका ऑक?सीजन लेवल कुछ सुधरा था, जिसके बाद सपोर्ट को कुछ घटाया गया था। पिछले चार दिन से उनको दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया गया जहां लगातार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आजम खां के शरीर में कैविटी के कारण चेस्ट इनफेक्शन से किडनी पर भी असर हुआ है। वह आइसीयू की क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं। फिलहाल उनका इलाज तीन से पांच लीटर के ऑक्सीजन प्रेशर पर चल रहा है। आजम खां सीतापुर जिला जेल में कोरोना वायरस संमक्रण की चपेट में आए थे। उसके बाद उनको बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के साथ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराय गया था। नौ मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब्दुल्ला आजम खां को इसके कहर से उबर गए हैं, लेकिन आजम खां की हालत गंभीर हो गई है।

पंजाब कांग्रेस की कलहः सक्रिय हुआ आलाकमान, तीन नेताओं की कमेटी बनाई, रावत ने जाखड़ पर कही बड़ी बात

चंडीगढ़ । पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जाग गय है। पंजाब कांग्रेस में कलह हो को दूर करने के लिए पार्टी आलाकमान सक्रिय हो गया है। आलाकमान ने विवाद के हल के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल को शामिल किया गया है। दूसरी ओर, हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा कि जाखड़ को हटाने का पार्टी का कोई इरादा नहीं है।

पिछले लंबे समय से कांग्रेस में चल रहे घमासान पर नकेल कसने के लिए पार्टी हाई कमान ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। जिसमें पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत , मल्लिकार्जुन खड़गे और जय प्रकाश अग्रवाल को शामिल किया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कमेटी बनाए जाने की पुष्टि की है। बेअदबी कांड समेत अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के राज्य सभा सदस्यों, मंत्रियों और विधायकों की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बढ़ रही खींचतान को लेकर पिछले दो महीनों से लगातार खबरें सुर्खियों में रही हैं । इसका असर 2022 के चुनाव में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री से नाराज पार्टी का एक वर्ग अपनी बात को राहुल गांधी के सामने रखने के लिए लंबे समय से समय मांग रहा है। इसको लेकर मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, परगट सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू आदि के बीच भी बैठकें हो चुकी हैं। पहले इन नेताओं की राहुल गांधी से वर्चुअल बैठक करवाने की खबरें आ रही थीं लेकिन इन नेताओं की जिद थी कि वह आमने सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे।

इन नाराज विधायकों की समस्या आदि के बारे में जानने और उसका हल सुझाने के लिए हाई कमान ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, मल्लिकाअर्जुन खड़गे और जयप्रकाश अग्रवाल शामिल हैं। कमेटी सभी विधायकों और सीनियर नेताओं के साथ बात करेगी। पूरे मामले में कांग्रेस के महासचिव व पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में चल रही अंतरकलह को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ को बदलने को लेकर अभी हमारा कोई इरादा नहीं है।

यास तूफान ने बिहार में मचाई भारी तबाही, कई पीपा पुल टूटे, घर गिरे और सात मरे

पटना । चक्रवात यास ने बिहार में भी भारी तबाही मचाई है। लगातार तेज बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। पीपा पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई मकान गिरे हैं। सात लोगों की मौत हुई है। इनमें पटना, दरभंगा, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, गया और भोजपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृत व्यक्यिों के प्रति गहरी शोक संवेदना जताई है। उन्होंने मृत लोगों के आश्रितों व परिजनों को चार-चार लाख मुआवजा और घायलों के समुचित इलाज का देने का निर्देश दिया है।

बिहार -यूपी को जोडने़ वाले पीपा पुल टूटा - राजधानी में पटना को वैशाली से जोडने़ वाले भद्र घाट पर पीपा पुल का एप्रोच रोड धंस गया। वाहनों का परिचालन शुक्रवार की सुबह से अगले दो दिनों के लिए रोक दिया गया। वैशाली के राघोपुर में तेज बारिश के कारण रुस्तमपुर पीपापुल क्षतिग्रस्त हो गया। भोजपुर के आरा, जगदीशपुर, गड़हनी, पीरो एवं शाहपुर अंचलों में डेढ़ दर्जन से अधिक मिट्टी के घर ध्वस्त हो गए। बड़हरा के मौजमपुर-महुली घाट स्थित बिहार -यूपी को जोडने़ वाले पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया है। एहतियात के तौर पर पुल के एक भाग को खोल दिया गया है। यूपी बिहार को जोडने़ वाले हाजीपुर टू गाजीपुर एनएच पर जय प्रभा सेतु की एप्रोच सड़क मांझी के दक्षिणी छोर पर ध्वस्त हो गई है। सेतु से होकर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है।

अस्पतालों में भरा पानी, एम्स पहुंचने में छूटा पसीना- यास तूफान के कारण राजधानी में लगातार दूसरे दिन बारिश के कारण शुक्रवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित कई अस्पतालों में पानी भर गया। इससे चिकित्सकर्मी परेशान रहे। हालांकि, बारिश के कारण रोगियों व टीकाकरण के लिए कम लोगों के आने से चिकित्साकर्मी मेज पर पांव रखकर बैठे दिखे। वहीं, एम्स जाने वाली सड़क पर दो फीट से अधिक जलजमाव से

वहां भर्ती मरीजों के स्वजन परेशान रहे। बताते चलें कि एम्स में कोरोना व ब्लैक फंगस के करीब ढाई सौ रोगी भर्ती हैं। एम्स का प्रवेश द्वार पर भी बारिश का पानी जमा था। इससे चिकित्साकर्मियों को भी अस्पताल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि राजधानी के कंकड़बाग स्थित जयप्रभा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भूतनाथ रोड़ स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी करीब दो फीट पानी भरा था।

तेज बारिश के कारण कोविड अस्पताल एनएमसीएच में सबसे निचली सतह पर स्थित मेडिसिन विभाग में पानी प्रवेश कर गया। यहां के कोरोना वार्ड में जलजमाव की संभावना को देखते हुए भर्ती लगभग डेढ़ दर्जन कोरोना मरीजों को देर रात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर स्थित मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दवा वितरण काउंटर की ओर से विस्तारित सेंट्रल इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अस्पताल परिसर में पानी लबालब भरा होने से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मरीजों और स्वजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

थाना का छत गिरा, बाल-बाल बची पुलिस- सारण में गंडक का जलस्तर बढने़ से तटबंध पर खतरा हो गया है। अमनौर प्रखंड में आधा दर्जन जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। तरैया प्रखंड में भी कई जगह बांध कमजोर हो गया है। औरंगाबाद जिले में मुफस्सिल थाना की भवन की छत अचानक टूटकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि कि काम कर रहे पुलिस पदाधिकारी बच गए। बक्सर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाई के कर्मी जर्जर आवास का छज्जा टूटकर गिरने से अफरातफरी मच गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर महताब आलम मामूली जख्मी हो गए।

सोन नदी में छोड़ा गया पानी ॑

रोहतास के डेहरी आन सोन में वर्षा से सोन नदी उफान पर है। झारखंड के मोहम्मदगंज स्थित भीम बराज से शुक्रवार को डेढ़ लाख क्यूसेक पानी सोन में छोड़ा गया है। इंद्रपुरी बराज पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं।

इनकी हुई मौत-बेगूसराय मे तेघड़ा थाना क्षेत्र की पिपरा दोदराज पंचायत के नोनपुर गांव में एक घर गिर गया , जिसके कारण उसके अंदर सो रही 71 वर्षीया गीता पासवान की मौत हो गई। परिवार के पांच अन्य सदस्य घायल हो गए हैं। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के संगम टोला गांव में मकान का छप्पर और दीवार गिरने से दबकर 54 वर्षीय भारत भूषण उर्फ शेखु सिंह की मौत हो गई। पटना जिले के नौबतपुर में एक मकान का छज्जा गिरने से इसमें दबकर रुस्तमगंज निवासी 31 वर्षीय नागेंद्र पासवान की मौत हो गई। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव में जलजमाव के कारण गड्ढें में डूबने से होमगार्ड के जवान सूबेलाल पासवान के 14 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार की मौत हो गई है। इसके अलावा औद्योगिक थाना क्षेत्र के छोटी युसुफपुर मोहल्ला निवासी पंकज पासवान औश्र उनके पुत्र मिथिलेश पासवान की गड्ढ़े में डूबने से मौत हो गई है।

हैदराबाद में कोविड -19 के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क पर ऑरोनावायरस की पेंटिंग।

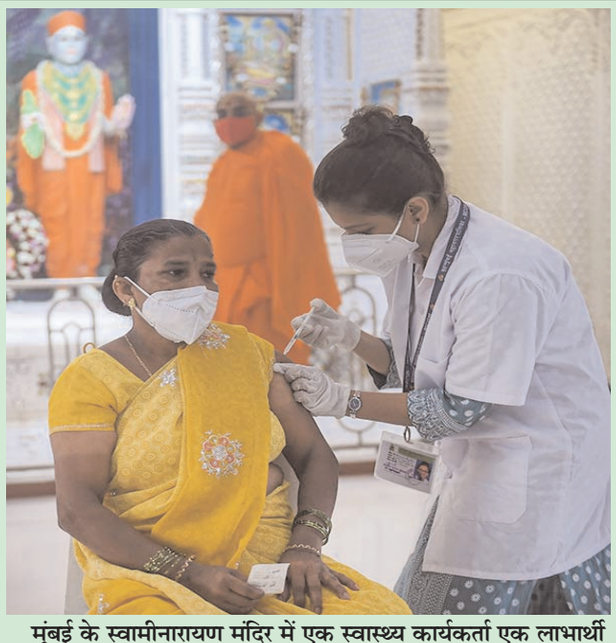

मुंबई के स्वामीनारायण मंदिर में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक लाभार्थी महिला को कोविड -19 वैक्सीन की खुराक देती हुई।

कोच्चि में समुद्र के किनारे एक मछुआरा दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले मछली पकड़ते हुए।

जवाहर नवोदय विद्यालय का कार्यालय अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

उदयपुर । राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के बुड़वा गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय अधीक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने स्कूल में कराए गए रंगाई और पुताई के बकाया 85 हजार रुपये के बिल दस फीसद रिश्वत मांगी थी। शनिवार को जैसे ही उन्होंने रिश्वत के 8500 रुपये लिए, उन्हें एसीबी की टीम ने दबोच लिया। रिश्वत लेते पकड़े गए कार्यालय अधीक्षक राजेश खन्ना मूलतः भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के कोलीवाड़ा के रहने वाले हैं और उनके आवास पर भी एक टीम जांच के लिए भेजी गई है।

खन्ना के खिलाफ बुड़वा, बागीदौरा निवासी ठेकेदार जगजी पटेल ने दो दिन पहले शिकायत की थी कि उसने जवाहर नवोदय विद्यालय में रंगाई और पुताई का काम किया था। इसके एवज में उसके 85 हजार रुपये का बिल बकाया था। जिसे पास करने के एवज में उसने दस फीसद राशि बतौर रिश्वत की मांग की। इसके लिए उसने इनकार किया तो उसने बिल रोक दिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया और रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर शनिवार सुबह स्कूल समय में रिश्वत की राशि लेकर ऑफिस अधीक्षक राजेश खन्ना के पास ठेकेदार जगजी को भेजा। खन्ना ने रिश्वत की राशि अपने टेबल की दराज में छिपाकर रख दी थी।

जिसे बरामद करने के साथ ही खन्ना को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही, एसीबी की टीम ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह सोडा ने बताया कि कार्यालय अधीक्षक के पास मौजूद उन सभी फाइलों की जांच की जा रही है, जिनके जरिए पहले स्कूल में कराए गए कार्यों के एवज में भुगतान किया गया। उन कार्यों के एवज में भी कार्यालय अधीक्षक के रिश्वत लिए जाने की आशंका जताई गई है। इस मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

वासुदेव देवनानी का आरोप, राजस्थान सरकार ने केंद्र से मिले 1500 वेंटिलेटर नहीं चलाए; कबाड़ में पड़ी रहीं एंबुलेंस

अजमेर । पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मिले वेंटिलेटरों का उपयोग नहीं करने से अनेक मरीजों की जानें चली जाने और आधी से ज्यादा एंबुलेंस कबाड़खाने में पड़ी रहने के लिए सीधे तौर पर राज्य की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। देवनानी ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से करोड़ों रुपये लागत के 19 सौ वेंटिलेटर राजस्थान को दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनमें से 15 सौ वेंटिलेटरों का उपयोग महज इसलिए नहीं किया, क्योंकि इन वेंटिलेटरों पर पीएम केयर फंड का लेवल लगा हुआ था। इसका यह मतबल यह हुआ कि कांग्रेस सरकार को मरीजों की जान बचाने की चिंता नहीं है और उसका मकसद केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना है।

तकनीशियनों को भी प्रशिक्षण नहीं दिया -देवनानी ने कहा कि जब वेंटिलेटरों के उपयोग की पड़ताल होने लगी, तो इन वेंटिलेटरों को खराब बताया जाने लगा, जबकि यही वेंटिलेटर अन्य राज्यों में बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और मरीजों की जानें बचाई गई हैं। उन्हें यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कांग्रेस मरीजों और आमजन के हितों की कीमत पर ओछी राजनीति क्यों करती है। वेंटिलेटर चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष से आएं या कोई दानदाता भेंट करे या राज्य सरकार खरीदे, उनका उपयोग मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वेंटिलेटरों का उपयोग नहीं करने के मकसद से इन्हें संचालित करने के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षण भी नहीं किया। यदि सरकार समय रहते तकनीशियनों को प्रशिक्षण देकर इन वेंटिलेटरों का उपयोग करती, तो अनेकों मरीजों का जीवन बचाया जा सकता था।

एंबुलेंस के अभाव में परेशान हुए ग्रामीण- उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब सवा सात सौ एंबुलेंस (108 सेवा) हैं। इनमें से आधी से ज्यादा कबाड़खाने में पड़ी हुई हैं। कोरोना महामारी के भारी संकटकाल में भी इन एंबुलेंस की चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा सुध नहीं ले पाए। यदि इन

एंबुलेंस को ठीक कराकर उपयोग में किया जाता तो आमजन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों मरीजों को समय रहते अस्पतालों में पहुंचाया जा सकता था। एंबुलेंस के अभाव में ग्रामीणों को अपने परिवार के मरीज को बैलगाड़ियों, ठेलों और टैक्टरों के अलावा कंधों पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। इस स्थिति में कुछ मरीजों ने तो अस्पताल पहुंचने से दम तोड़ दिया था। यदि एंबुलेंस होती, तो मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचा कर उनकी जान बचाई जा सकती थी।

सरकार सुधारें व्यवस्थाएं, बचाए मरीजों की जान- देवनानी ने कहा कि इन एंबुलेंसों के कबाड़खाने में पड़े रहने सरकार की प्रशासनिक अक्षमता का गंभीर उदाहरण है। इससे यह जाहिर हो जाता है कि सरकार कोरोना से निपटने और मरीजों की जान बचाने के लिए कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी भी चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार कर मरीजों की जान बचाने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए।

वीर सावरकर हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोतः देवनानी

पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में से क्रांतिकारी और महान शब्द हटाने से क्रांतिकारी विनायक दामोदर वीर सावरकर का कद कभी भी घटने वाला नहीं है। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे। वे हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। देवनानी ने वीर सावरकर की जयंती पर अपने निवास पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा के शासनकाल में वीर सावरकर को शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पाठ्यक्रम में से सावरकर के नाम से क्रांतिकारी और महान शब्द हटाने के साथ अनर्गल बातें जोड़ते हुए वीर सावरकर का कद घटाने का काम किया है। किंतु वीर सावरकर का कद इतना बड़ा है कि उनका कद घटाने का कोई भी प्रयास बौना साबित होता है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर वह महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों की किसी भी कार्यवाही के आगे झुके नहीं। अंग्रेजों ने उन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा सुना कर सेलुलर जेल की काल कोठरी में डाल दिया था, घाणी में बैलों की जगह उन्हें जोता गया, इसके बावजूद वीर सावरकर वाकई में वीर थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के हर जुल्मों को सहा।

वीर सावरकर ने 1857 के आजादी आंदोलन पर पुस्तक लिखी, किंतु अंग्रेजों ने उसे छपने से पहले ही जब्त कर लिया था। अंग्रेजों और कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया। कांग्रेस कभी भी क्रांतिकारियों और महान पुरुषों की पक्षधर नहीं रही। केवल एक ही परिवार की पूजा करना कांग्रेस का स्वभाव रहा। देवनानी ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो अतीत में भी महान पुरुषों और क्रांतिकारियों को सम्मान देती रही है और आगे भी देती रहेगी। भाजपा की हर रीति-नीति में इन महान पुरुषों और क्रांतिकारियों की प्रेरणा शामिल होती है। यही कारण है कि भाजपा लगातार प्रगति करती हुई देशभर में शासन करने वाली बड़ी पार्टी बन गई है।

वीर सावरकर से कार्यकर्ता लें प्रेरणा- उन्होंने कहा कि ''मातृभूमि के लिए जीना और मर जाना ही जीवन की सार्थकता है'', वीर सावरकर का यह विरोचित मंत्र देश की भावी पीढ़ियों को राष्ट्र उत्थान एवं सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। देवनानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे महान पुरूषों और क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज की सेवा करें। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम शर्मा, पार्षद रूबी जैन, पूर्व पार्षद अनीश मोयल, रचित कच्छावा आदि भी मौजूद रहे।

गुजरात में बना 900 बेड वाला कोविड अस्पताल, ड्राईव-थ्रू वैक्सीन भी उपलब्ध

अहमदाबाद । वाइब्रेंट गुजरात एवं कई अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के गवाह बने महात्मा मंदिर गांधीनगर। यहां 900 बेड की स्पेशल कोविड-19 अस्पताल का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी शनिवार दोपहर इसका निरीक्षण करने पहुंचे। रूपाणी ने कहा की गुजरात में सवा लाख युवाओं को हर रोज टीका लगाया जा रहा है साथ ही निजी अस्पतालों की भागीदारी से 1000 की फीस लेकर भी ड्राईव-थ्रू वैक्सीन की सुविधा भी दी जा रही है।

सरकार ने तीन करोड़ टीके का आर्डर दिया है जिसकी डिलीवरी समय-समय पर हो रही है। टीके के ग्लोबल टेंडर की फिलहाल सरकार जरूरत महसूस नहीं कर नहीं है इसलिए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने ग्लोबल टेंडर काकोई नतीजा नहीं निकला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी को मुफ्त टीका देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन जरूरतमंद इन निजी अस्पताल की भी मदद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन, वेंटीलेटर सहित आईसीयू जैसी तमाम आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त इस हॉस्पिटल का निर्माण डीआरडीओ ने गुजरात सरकार की मदद से किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में धन्वंतरी कोविड-19 हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में गांधीनगर में भी रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की मदद से अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। गांधीनगर, पाटण, मेहसाणा सहित उत्तर गुजरात के आधा दर्जन जिलों एवं सैकड़ों गांव के कोरोना संक्रमितों को यहां तमाम मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी।

अस्पताल में मौजूद हैं ये सुविधायें

900 बेड के इस अस्पताल में 350 बेड वेंटिलेटर सुविधाओं वाले हैं जबकि 350 ऑक्सीजन की सुविधा वाले हैं। 200 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधाओं वाले तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार ने यहां 54 टन का ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया है ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज को परेशानी ना हो। अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पतालों में इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी। उत्तर गुजरात तथा गांधीनगर जिले के सैकड़ों गांव के मरीजों को महात्मा मंदिर में ही भर्ती किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री रूपाणी ने यहां बताया कि राज्य में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इसके केस लगातार घट रहे हैं लेकिन लोगों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना समाप्त हो गया है। राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए पूरी तरह राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

तीसरी लहर को देखते हुए सरकार तैयार- मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। मेडिकल विशेषज्ञों सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं आला अधिकारियों की एक कोर कमेटी बनाई गई है जो मेडिकल स्टाफ, इंजेक्शन, कोविड हॉस्पिटल, सहित ऑक्सीजन, वेंटीलेटर व अन्य मेडिकल सुविधाओं की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहां की सरकार ने किसी भी तरह के खर्च की चिंता किए बिना लोगों को मेडिकल सुविधाएं एवं दवाएं उपलब्ध करा रही है।

महिला को 10 मिनट में दो बार लग गई वैक्सीन!

जयपुर। किसी महिला को 10 मिनट में दो वैक्सीन लगाने का मामला शायद देश में पहली बार राजस्थान के दौसा जिले में सामने आया है। दौसा जिले के खैरवाल गांव की 43 वर्षीय किरण शर्मा अपनी बेटी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंची। उन्हें 10 मिनट के अंदर ही कोवैक्सीन की दो डोज लगा दी गई। हालांकि किरण को हल्का बुखार ही आया और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल, नांगर बैरसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची किरण सीधे वैक्सीनेशन में चली गई, जहां एक नर्स ने उसे टीका लगा दिया और कुछ देर वहीं बैठने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद एक अन्य महिलाकर्मी आई और उसने किरण से आधार कार्ड की फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर मांगे। ये दोनों लेने के बाद महिलाकर्मी ने उसे फिर टीका लगा दिया। पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर गई किरण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक साथ टीका कितनी बार लगाया जाता है, इस कारण वह वहां शांत रही।

घर वापस आकर किरण ने दो बार सुई लगाने की बात अपने पति रामचरण शर्मा को बताई। किरण की बात सुनकर रामचरण शर्मा और उनके बच्चे परेशान हो गए। रामचरण शर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्होंने पत्नी के दो बार टीका लगने की बात बताई, लेकिन स्टाफ ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। वे फिर आए और पत्नी से दोबार पूछा कि कितनी बार हाथ में इंजेक्शन लगा था तो उसने दो बार बताया। यह बात सुनकर परिवार हैरान हो गया। इस बारे में स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. नीलम मीणा से जब जानकारी की गई तो उन्होंने ऐसा होने से इनकार कर दिया। मीणा ने बताया कि किसी को भी दो डोज एक साथ नहीं लगाई गई। किरण को वैक्सीन लगाने के लिए पिंच किया गया तो उन्हें खून आ गया। इसके बाद उन्हे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर पिंच किया गया और वैक्सीन लगाई गई। वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि जब सभी के एक बार पिंच किया गया तो किरण को दो बार क्यों किया गया। किरण ने अपने खून आने से इनकार किया है।

नौसेना प्रमुख बोले- युद्ध की बदलती प्रकृति के लिहाज से सेना के तीनों अंगों की एकजुटता बेहद जरूरी

पुणे । चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में मौजूदा वक्त में युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए तीनों सेनाओं की एकजुटता की जरूरत बेहद महत्वपूर्ण है। नौसेना प्रमुख ने पुणे के खडकवासला में शनिवार की सुबह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अकादमी के 140वें पाठ्यक्रम के पासिंग आउट परेड को संबोधित किया।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा वक्त में युद्ध की प्रकृति बदल रही है जिससे तमाम विपरित परिस्थितियों में थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर जैसे सभी क्षेत्रों की एकजुटता और भागीदारी अहम हो जाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही तीनों सेवाओं का एक साथ आना पहले की तुलना में अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य मामलों के विभाग, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जैसे पद की शुरुआत के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा सुधार हुए हैं।

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही थियेटर कमान का गठन होगा। यह सेना के

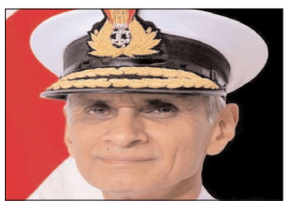

तीनों अंगों की भागीदारी वाला कमान है। तीनों सेवाओं की विशिष्ट भूमिका के लिहाज से प्रत्येक सेवा की परंपराएं, पहचान, वर्दी और तौर-तरीकों की उपयोगिता है लेकिन मौजूदा वक्त के जटिल युद्धक्षेत्र में तालमेल और प्रभावी कदम के लिए सैन्य बलों का एक साथ आना सर्वोपरि है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 72 वर्षों से एनडीए एकजुटता का प्रतीक रहा है। इसका अस्तित्व एकजुटता के मौलिक मूल्यों पर आधारित है। यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आधारभूत सिद्धांत है। करमबीर सिंह ने कहा कि सभी कैडेट्स को याद रखना चाहिए कि भविष्य का युद्ध चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो प्रभावी नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत क्षमताएं बेहद मायने रखती हैं।

वडोदरा में डीजे पर डांस के आरोप में छह लोग गिरफ्तार

अहमदाबाद । गुजरात के सूरत में पुलिस निरीक्षक की विदाई पार्टी करने वाले बिल्डर से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि निरीक्षक को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। उधर, वडोदरा में विवाह समारोह में डीजे पर डांस करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के सूरत वड़ोदरा तथा कच्छ में कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं विदाई समारोह कहीं जन्मदिन की पार्टी तो कहीं विवाह समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। सूरत में गत बुधवार रात्रि सिंघनपोर इलाके में एक फार्म हाउस पर पुलिस निरीक्षक एपी सलैया की विदाई पार्टी आयोजित करने के मामले में पुलिस ने आरोपित सलैया तथा पार्टी का आयोजन करने वाले एक बिल्डर रमेश कानाणी को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया के निर्देश पर सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर निरीक्षक को पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं।

पकड़ा गया दुष्कर्मी, बीते छह माह से शेल्टर होम में नाबालिगों के साथ हो रहा था घिनौना काम

उदयपुर । चित्तौड़गढ़ के बाल कल्याण समिति के शेल्टर होम में रह रही बालिकाओं के साथ लंबे समय से हो रहे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां हैरान करने वाली यह बात सामने आई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके शेल्टर होम में हंगामा मचाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन शेल्टर होम प्रबंधन ने उन्हें बालिकाओं से दुष्कर्म की बात नहीं बताई। मिली जानकारी के शेल्टर होम में पिछले छह महीने से रह रही नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

लेकिन पुलिस यह जानकर हैरत में रह गई कि महेंद्र सिंह वहीं व्यक्ति है, जिसके शेल्टर होम प्रबंधन ने पिछले सप्ताह उसके हंगामा किए जाने की सूचना पर उन्हें बुलाया था। पुलिस का कहना है कि शेल्टर होम प्रबंधन को एक पखवाड़े से बालिकाओं से दुष्कर्म की जानकारी थी लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह के आरोपी होने की बात नहीं बताई। इधर, समिति अध्यक्ष रमेश दशोरा का कहना है कि 20 मई को पुलिस को बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की सूचना दी थी और उसकी जांच के आदेश भी दिए लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई।

जब पीड़ित दो बालिकाओं की बड़ी बहन ने मामला दर्ज कराया तब जाकर पुलिस सक्रियहुई। इधर, सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह का कहना है कि 19 मई को कंट्रोल रूम के जरिए शेल्टर होम पर एक व्यक्ति के हंगामा करने की सूचना मिली थी कि मौके पर जाब्ता भेजा गया था लेकिन वहां मौजूद पदाधिकारी ने सिर्फ बच्चियों को ले जाने की बात कही थी। आरोपी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी या रिपोर्ट नहीं दी थी। बाद में बाल कल्याण समिति का पत्र मिला तब जाकर मामला दर्ज किया गया।

अपनी विवाहित प्रेमिका की दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महेंद्र सिंह से खुलासा हुआ कि उसने प्रेमिका की सबसे बड़ी बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया। जिसने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसी ने अपने पिता को महेंद्र सिंह के अत्याचार के बारे में जानकारी दी थी लेकिन पिता अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को बेचने के फिराक में थे।

भरतपुर में बीच सड़क पर डॉक्टर दंपति को गोली से भूना, दोनों की मौत

जयपुर । राजस्थान के भरतपुर जिले में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। सांसद रंजीता कोली पर हमले के एक दिन बाद भरतपुर शहर की बीच सड़क पर बाइक सवार दो युवकों ने डॉक्टर दंपति को गोलियों से भून दिया। दोनों युवकों ने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा के उस समय गोली मारी जब वे अपनी कार से मंदिर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों की पहचान कर ली है। इनमें एक आरोपित डॉ.सुदीप गुप्ता की पूर्व प्रेमिका का भाई अनुज और दूसरा उसके मामा का लड़का है।

पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि दोनों आरोपित धौलपुर के रहने वाले हैं। जल्द ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर दंपति शुक्रवार शाम अपने अस्पताल से मंदिर जा रहे थे कि बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से ओवरटैक करते हुए कार के आगे आकर बाइक लगा दी। मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मुंह पर कपड़ा बांधे दोनों आरोपित कार के आगे बाइक खड़ी कर के डॉ.सुदीप के पास गए उन्होंने कांच खोलकर रास्ता रोकने का कारण पूछा कि इतनी ही देर में एक युवक ने दंपति पर पिस्तोल से फायरिंग कर दी। दोनों के कुल 6 गोलियां लगी। दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के भरतपुर जिले में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। सांसद रंजीता कोली पर हमले के एक दिन बाद भरतपुर शहर की बीच सड़क पर बाइक सवार दो युवकों ने डॉक्टर दंपति को गोलियों से भून दिया। दोनों युवकों ने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा के उस समय गोली मारी जब वे अपनी कार से मंदिर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों की पहचान कर ली है। इनमें एक आरोपित डॉ.सुदीप गुप्ता की पूर्व प्रेमिका का भाई अनुज और दूसरा उसके मामा का लड़का है।

पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि दोनों आरोपित धौलपुर के रहने वाले हैं। जल्द ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर दंपति शुक्रवार शाम अपने अस्पताल से मंदिर जा रहे थे कि बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से ओवरटैक करते हुए कार के आगे आकर बाइक लगा दी। मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मुंह पर कपड़ा बांधे दोनों आरोपित कार के आगे बाइक खड़ी कर के डॉ.सुदीप के पास गए उन्होंने कांच खोलकर रास्ता रोकने का कारण पूछा कि इतनी ही देर में एक युवक ने दंपति पर पिस्तोल से फायरिंग कर दी। दोनों के कुल 6 गोलियां लगी। दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।

पूर्व प्रेमिका की मौत से जुड़ा है मामला- दरअसल, डॉक्टर दंपति के अस्पताल में एक साल पहले धौलपुर निवासी दीपा गुर्जर नाम की एक युवती रिसेप्शन पर नौकरी करती थी । इस दौरान डॉ.सुदीप के उससे प्रेम संबंध हो गए थे। उन्होंने उसे भरतपुर में ही अपना एक विला दिया,जिसमें वह अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी । इस बात की जानकारी डॉ.सुदीप की पत्नी सीमा को लगा तो एक साल पहले अपनी सास सुरेखा के साथ विला में पहुंची। वहां दीपा गुर्जर के साथ सीमा और उसकी सास का झगड़ा हुआ था। इस दौरान सीमा ने अपनी सास के साथ मिलकर दीपा गुर्जर और उसके बेटे को रसोई में बंद कर घर में स्प्रीट छिड़कर आग लगा दी थी । जिससे दोनों मां-बेटे की जिंदा जलने से मौत हो गई थी । इस मामले में डॉक्टर दंपति को सजा हुई थी । वे कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे ।

ओडिशा सरकार ने कोरोना की दवा 2-डीजी के पांच हजार पाउच का दिया आर्डर

भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार ने डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना संक्रमण के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवा 2-डीजी के पांच हजार पाउच खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप्त महापात्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में यह दवा काफी उपयोगी साबित हो रही है। इससे गंभीर मरीजों के इलाज में सुविधा होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित दवा 2-डीजी कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी उपयोगी होगी। इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) ने मध्यम से गंभीर कोरोना वायरस रोगियों में एक सहायक चिकित्सा के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी जल्द ही खुले बाजार में मिलेगी। (डीआरडीओ) की कोरोना दवा 2-डीजी सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को कम कीमत पर मुहैया कराई जाएगी। डॉ रेड्डीज लैब द्वारा विकसित डीआरडीओ की 2-डीजी एंटी-कोविड 19 दवा की कीमत 990 रुपये प्रति पाउच रखी गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकार को रियायती मूल्य पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक तो लग गई, मगर कोरोना से हो रही मौत का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रदेश में 7216 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11 हजार 551 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। पिछले पांच दिन में ओडिशा में 167 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। संक्रमित पाए गए सात हजार 216 लोगों में से चार हजार 41 लोग क्वारंटाइन से हैं, जबकि तीन हजार 175 स्थानीय लोग संक्रमित हुए। प्रदेश में सर्वाधिक 1091 मरीज कटक जिले मिले, जबकि खुर्दा जिले से 809, केन्द्रापड़ा जिले से 487, ढेंकानाल जिले से 428, अनुगुल जिले से 409 लोग संक्रमित पाए गए।

पूजा हेगड़े ने बताया 'सर्कस' में रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के साथ काम करने का अनुभव

साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने बेहद कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिसमें मिस यूनिवर्स इंडिया रनर अप होने से लेकर इंडस्ट्री में कुछ बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। पूजा ने हिन्दी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 2016 में रितिक रोशन की फिल्म 'मोहनजो दाड़ो' से की थी। अब अब रोहित शेट्टी की फिल्म 'सर्कस' में रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाली हैं। कोरोनावायरस की दूसरी लहर आने से पहले और लॉकडाउन लागू होने से पहले पूजा हेगड़े अपनी फिल्मों के लिए नॉन-स्टॉप शूटिंग कर रही थीं। इन्हीं फिल्मों में से एक सर्कस थी जहां वह पहली बार रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान रोहित और रणवीर के साथ शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए पूजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी फिल्म के सेट पर इतनी हंसी हूं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक पार्टी में हूं और काम बस साइड में हो रहा था। यही उस इक्वेशन की सुंदरता है जिसे हम सभी साझा करते हैं। सेट की एनर्जी और वाइब बहुत अच्छी थी। जब पिछले साल लॉकडाउन में ढील दी गई थी, पूजा ने सर्कस में अपने हिस्से की शूटिंग के लिए मुंबई का रुख किया और साथ ही वह राधे श्याम व मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शूटिंग शेड्यूल भी मैनेज कर रही थीं। इस साल आचार्य और थलपति 65 भी सूची में शामिल हो गईं है, जिसके कारण उनका शेड्यूल और भी कठिन था, जबकि उन्होंने ऊटी में सर्कस के लिए कुछ दिन शूटिंग की थी। उन्होंने अभी तक सलमान खान के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की है। पूजा न केवल बॉलीवुड में बल्कि तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी प्रमुख नामों में से एक है, जिनकी अखिल भारतीय अपील है और उनका लाइनअप उसी का प्रमाण है। पैन-इंडिया स्टार कई बिग टिकट फिल्मों में नज़र आएंगी, जिनमें रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की फ़िल्म सर्कस, सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दीवाली, प्रभास के साथ पैन-इंडिया फिल्म राधे श्याम, राम चरन के साथ आचार्य, अखिल अक्किनेनी के साथ मोस्ट एलिजिबल बैचलर और थलपति विजय के साथ थैलापैथी 65 शामिल है।

मलाइका अरोरा के और करीब आए अर्जुन कपूर

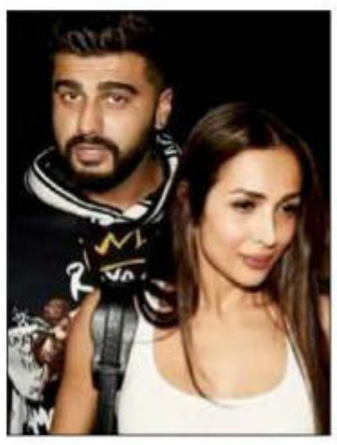

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा की जोड़ी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। दोनों अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते रहते हैं। वहीं अब अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के और करीब आ गए हैं। दरअसल, अर्जुन ने मलाइका के घर के करीब एक नया घर खरीदा है। अर्जुन कपूर ने बांद्रा इलाके की पॉश बिल्डिंग में 20 करोड़ का 4BHK स्काईविला विला खरीदा है। बताया जा रहा है कि इस घर में सभी सुविधाएं हैं, इसमें एक पूल और

गोल?फ एरिया भी है। इस विला को खरीदते ही अर्जुन कपूर अपने मलाइका अरोरा के पड़ोसी बन गए हैं। मलाइका ने भी इसी बिल्डिंग में अपना घर लिया है। बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ही अपना नया घर खरीदा था। मलाइका अरोरा के साथ-साथ अर्जुन कपूर अब सोनाक्षी सिन्हा के भी पड़ोसी हो गए हैं। बता दें कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा सोशल मीडिया पर अक्सर अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन कपूर ने कहा था कि उन्हें मलाइका की पूर्व जिंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।

जीनत अमान हैं सोमी की बॉलीवुड में सबसे करीबी दोस्त

'अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो हमेशा आपकी तरफ हो, आपके साथ सम्मान से पेश आए और आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपें, तो यह सच्ची दोस्ती है'

कहते हैं कि सच्चे दोस्तों के साथ जीवन बेहतर होता है, इसलिए यदि आप जीवन भर अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप भाग्यशाली हैं। सोमी अली भी इससे सहमत हैं लेकिन कहती हैं कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अभिनेता से मानवतावादी बनी सोमी, जिनके जीवन में सीमित करीबी दोस्त हैं, कठिन समय से गुजरी हैं और इसलिए बहुत सतर्क हो गई हैं।

जीवन में इस बात का अहसास देर से हुआ

दोस्ती महत्वपूर्ण है लेकिन किसी रिश्ते को समझने के लिए कुछ समय देना चाहिए कि क्या वह इसके लायक है। फ़यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेते हैं जो हमेशा आपकी तरफदारी करता है, आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, आपके साथ सम्मान से पेश आएगा, तो हाँ यह सच्ची दोस्ती है। लेकिन यह दुर्लभ है। आपके साथ पार्टी करने वाले सभी लोग आपके साथ भूखे नहीं रहेंगे। मुझे जीवन में बहुत देर बाद इसका एहसास हुआ, लेकिन कम से कम अब मुझे पता है।'

सुबह 4 बजे के दोस्त की अवधारणा पर विश्वास नहीं

सोमी कहती हैं, 'सुबह 4 बजे के दोस्त की अवधारणा में मैं विश्वास नहीं करती क्योंकि हर चीज के लिए मैं खुद पर निर्भर हूं। मैं एक मजबूत स्वतंत्र महिला हूं, और मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। आत्मनिर्भरता न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप कभी नहीं जानते कि कब कोई आपको त्याग सकता है, आपको चोट पहुँचा सकता है, पीठ में छुरा घोंप सकता है, हेरफेर कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है। मुझसे पूछो, मुझे पता है कि ऐसा होने पर कितना दर्द होता है।'

दोस्ती सुविधा का रिश्ता है

बॉलीवुड में सोमी की करीबी दोस्त जीनत अमान हैं। इंडस्ट्री में उनका और कोई दोस्त नहीं है। वे समय-समय पर उनसे बात करती हैं। बॉलीवुड में कई लोगों को लगता है कि दोस्ती सुविधा के रिश्ते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इससे सहमत हैं और उनके जीवन के इस पड़ाव पर दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है? तो सोमी जवाब देती हैं, 'सभी दोस्ती सुविधा के रिश्ते हैं, लेकिन यह दोनों तरह से काम करता है। अगर तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। हमारा पूरा अस्तित्व व्यापार और पसंद पर आधारित है। हमें केवल जानवरों और हमारे माता-पिता से बिना शर्त प्यार मिलता है।'

जीवन के इस पड़ाव पर सोमी पूरी तरह से संतुष्ट है। 'अगर मैं नए लोगों से मिलती हूं और मुझे लगता है कि वे सच्चे हैं, तो मैं उनका खुले हाथों से स्वागत करती हूं। लेकिन फिर, मेरी प्राथमिकता एनएमटी (No More Tears, सोमी का एनजीओ) है और इससे पहले कुछ भी नहीं आता है,' सोमी बात समाप्त करती हैं।

भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है

बॉलीवुड अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कम उम्र में भारत आ गईं अभिनेत्री एली अवराम का कहना है कि उन्होंने यहां रहकर बहुत कुछ सीखा है। अभिनेत्री मूल रूप से स्टॉकहोम, स्वीडन की रहने वाली हैं । वो कहती हैं कि भारत में उनके अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को बड़े पैमाने पर आकार देने में योगदान दिया है। एली ने बताया '' मुझे विश्वास की छलांग और कदम उठाने के लिए संघर्ष वास्तव मेंलायक रहा है, कम उम्र में भारत आने के लिए खुद पर बहुत गर्व है, क्योंकि इसने मुझे वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार

दिया है, जिसके पास बहुत अधिक वष्टिकोण हैं और जीवन और इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में समझ है। मैंने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है, और मैं धन्य महसूस करती हूं।''इस बीच, 'मलंग' और 'मिकी वायरस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं अभिनेत्री का कहना है कि जिस तरह से उनका करियर आकार ले रहा है, उससे वह खुश हैं। उन्होंने कहा '' बॉलीवुड में मेरे स्थान के संबंध में, मैं सिर्फ उन फिल्म निमार्ताओं को धन्यवाद नहीं करूंगी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, बल्कि भारतीय दर्शकों ने भी मुझे स्वीकार किया, सराहना की और समर्थन किया उनका भी धन्यवाद करूंगी। उनके प्यार के बिना मैं आज जहां हूं, वहां नहीं होती।''

5 साल बाद टीवी पर वापसी करने जा रहीं मोना सिंह

'जस्सी जैसी कोई नहीं' शो से घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह 5 साल बाद टेलीविजन पर वापसी करने जा रही हैं। मोना सिंह जल्द ही क्राइम शो 'मौका-ए-वारदात 2' को होस्ट करती नजर आएंगी। शो में उनके साथ एक्टर रवि किशन नजर आएंगे। इस शो में कई एपिसोड्स होंगे, जिसमें हर कहानी अलग दिखाई जाएगी। इस शो के लिए रश्मि देसाई के नाम पर भी विचार हुआ था और उनके बातचीत भी हुई थी लेकिन आखिरकार मोना सिंह को फाइनल कर लिया गया। इससे पहले मोना सिंह 9 साल पहले क्राइम थ्रिलर शो सीआईडी में काम कर चुकी है। इस खबर को कंफर्म करते हुए मोना सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, 'हां, ये सही है, मैं मौका-ए-वारदात का

हिस्सा हूं। क्राइम जोनर हमेशा से ही उत्सुकता बढ़ाता है और ये काफी मजेदार प्रोजेक्ट है और अभी हम शो की डिटेल्स पूरा करने पर काम कर रहे हैं। जैसे ही सभी तरह की फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी जगह फाइनल नहीं हुई है। बता दें कि मोना सिंह टीवी पर आखिरी बार पांच साल पहले 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' में नजर आई थीं। मोना सिंह ने टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत जस्सी जैसी कोई नहीं शो से की थी और बाद में झलक दिखला जा, राधा की बेटी कुछ कर दिखेंगी, और कवचज काली शक्तियों से जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। वह 3 इडियट्स, ऊट पटांग और जेड प्लस जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

कार्तिक आर्यन क्या कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं?

फिल्मों से कलाकार का अलग होना नई बात नहीं है, बरसों से ऐसा होता आया है। कई बार आधी फिल्म की शूटिंग करने के बाद कलाकारों ने फिल्म छोड़ कर निर्माता-निर्देशकों को करोड़ों की चपत लगाई है, लेकिन फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन का मामला इसलिए खास बन जाता है कि उन्होंने एक महीने से भी कम समय के अंतराल में बॉलीवुड के दो बड़े बैनर की फिल्में छोड़ दी या फिर उन्हें निकाल दिया गया है। हाल ही में कार्तिक शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की फिल्म 'फ्रैडी' से अलग हो गए हैं जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ जैसी बड़ी हीरोइन थी। कार्तिक ने ये ईमानदारी जरूर दिखाई कि साइनिंग अमाउंट दो करोड़ रुपये लौटा दिए, वरना कई कलाकार ये रकम डकार जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें व्हाइट मनी दी गई हो और इस वजह से कार्तिक के आगे कोई चारा न हो, वरना पुराने निर्माता इतनी चालाकी नहीं दिखा पाते थे। कुछ दिनों पहले इसी क्रिएटिव डिफरेंस के चलते करण जौहर की फिल्म 'दोस्ताना 2' से कार्तिक अलग हो गए थे। करण की इस ?फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग भी कार्तिक ने की थी। लगभग 20 करोड़ रुपये का नुकसान करण को हुआ है क्योंकि नए हीरो के साथ उन्हें फिर से ये सीन फिल्माना होंगे। शाहरुख के बैनर की फिल्म छोड़ने की अलग-अलग वजह बताई जा रही हैं। इस फिल्म को बनाने की योजना पिछले दो-तीन बरस से चल रही थी। इसी बीच कार्तिक की कुछ फिल्में सफल हो गईं और वे ज्यादा रकम मांगने लगे जो निर्माताओं को नामंजूर था। दूसरी बात क्रिएटिव डिफरेंस को लेकर आ रही है। कार्तिक स्क्रिप्ट में बदलाव करवाना चाहते थे जो मेकर्स को मंजूर नहीं था। किसी भी सितारे को फिल्म साइन करने के पहले कहानी सुनाई जाती है। रोल बताया जाता है और फिर पसंद आने पर कलाकार फिल्म के लिए हां कहता है। साइन करने के बाद कलाकार कहानी या स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग करता है तो यह पूरी तरह गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म साइन करने के बाद कलाकार की कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं। उसकी एक खास किस्म की छवि बन जाती है और इस छवि को ध्यान में रख कर कलाकार बदलाव की मांग करता है। रोमांटिक फिल्म कर रहे हीरो की एक्शन फिल्में हिट हो जाती हैं तो वह रोमांस में भी एक्शन दृश्यों को जगह देने की गुंजाइश ढूंढने लगता है। रीढ़विहीन निर्माता-निर्देशक इस मांग के सामने झुक जाते हैं या फिर सितारा बहुत बड़ा हो। कार्तिक अभी इतने बड़े सितारे नहीं बने हैं कि उनकी इस तरह की मांग मानी जाए। संभव है कि कार्तिक को गुमान हो गया हो उनके दम पर फिल्म चली हो और वे स्टार बन गए हैं। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती जगजाहिर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि करण की फिल्म छोड़ने के बाद कार्तिक को अपनी फिल्म से अलग कर शाहरुख ने अपनी दोस्ती निभाई है? बहरहाल धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज जैसे बैनर की फिल्म से जिस तरह से कार्तिक गैर पेशेवराना तरीके से अलग हुए हैं उससे उनके करियर पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। संभव है कि उनके इस व्यवहार से बड़े बैनर्स दूरी बना ले। संभव है कि कुछ कलाकार कार्तिक के साथ काम नहीं करें? कार्तिक इस तरह से कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहे हैं। उन्हें इस दिशा में ठीक से सोचना होगा क्योंकि बॉलीवुड में पिछड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। हर शुक्रवार नया हीरो आकर आपका प्रतिस्पर्धी बन जाता है।

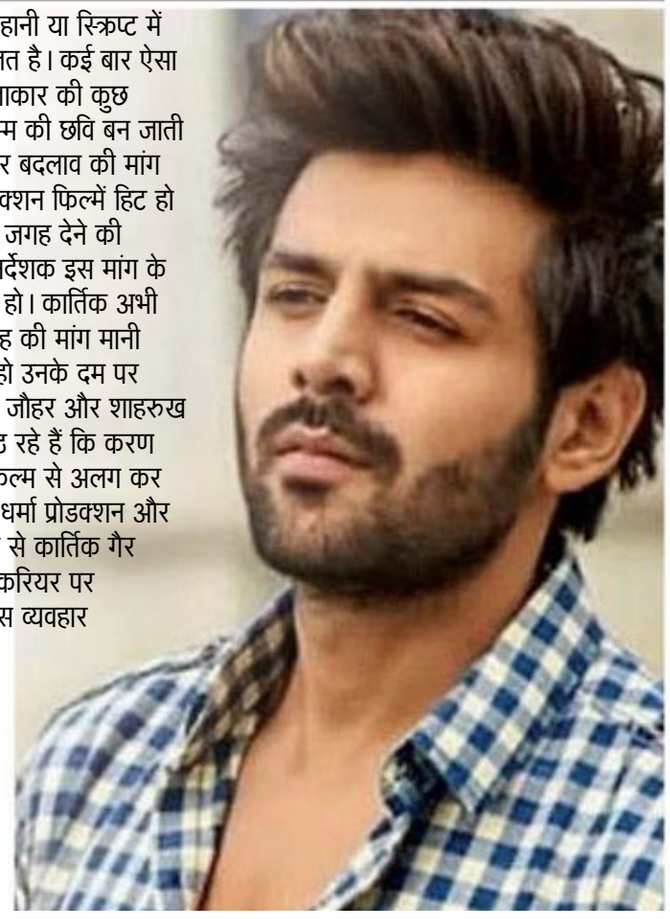

सर्बिया में खेले जा रहे एपीपी 250 ओपन सेमीफाइनल सिंगल्स टेनिस मैच में जीत के बाद खुशी जाहिर करते सर्बिया के नोवाक डोकोविक।

संजय मांजरेकर ने क्रिकेट से फ्री हिट हटाने का सुझाव दिया, तो अश्विन ने मांग ली फ्री बॉल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बीते दशक के दौरान सीमित ओवर के क्रिकेट में काफी बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर टी20 क्रिकेट के परवान चढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खेल को लोकप्रिय बनाने के लिहाज से कई नियमों में बदलाव किए। हालांकि, इसका फायदा गेंदबाजों के स्थान पर बल्लेबाजों को ज्यादा हुआ है। इस पर लंबे समय से बहस हो रही है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर का भी यही मानना है। उन्होंने हाल में ही क्रिकेट के नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। इसमें फ्री हिट और लेग बाय हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि फ्री हिट के नियम को क्रिकेट से हटा देना चाहिए क्योंकि, यह गेंदबाजों के लिए सही नहीं है। मांजरेकर ने अपने कॉलम में लिखा है कि फ्री हिट को मैं हटाना चाहता हूं, यह गेंदबाजों के लिए गलत है. आज जब टीवी अंपायर नो बॉल देखते हैं, तो एक गेंदबाज को लाइन से केवल एक सेंटीमीटर आगे होने पर भी सजा दी जाती है। मांजरेकर ने लिखा कि इस नियम के कारण गेंदबाज को अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ती है। साथ में एक अतिरिक्त रन भी बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में जुड़ता है। इसके अलावा बल्लेबाज को अगली गेंद पर फ्री हिट मिलती है, जिसमें वह आउट नहीं हो सकता। उन्होंने ट्विटर पर नियमों में बदलाव के बारे में अपने विचार पोस्ट किए और यूजर्स से सुझाव भी मांगे। उन्होंने लिखा- नमस्कार दोस्तो, आप मुझे बताएं कि मेरे इस कॉलम में खेल से जुड़े कुछ पहलुओं का जिक्र किया गया है, जो कम से कम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं। साथ ही, आप मुझे बताएं कि क्रिकेट देखने के अनुभव को बेहतर करने के लिए किन नियमों में बदलाव करेंगे। उनसे इस ट्वीट पर भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मजेदार जवाब दिया है। उन्होंने फ्री हिट का समर्थन करते हुए गेंदबाजों के लिए फ्री बॉल का नियम लागू करने की मांग की।

अश्विन ने लिखा कि संजय मांजरेकर, फ्री हिट मार्केटिंग का शानदार हथियार है और इसने सभी फैंस के दिमाग पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। ऐसे में गेंदबाजों के लिए फ्री बॉल का नियम जोड़ा जाना चाहिए, जब कोई बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर एंड को जल्दी छोड़ता है तो, उस गेंद पर अगर विकेट मिलता है तो गेंदबाज ने कुल जितने रन दिए हैं। उसमें से 10 रन घटा देने चाहिए। मांकडिंग का समर्थन करने वाले अश्विन ने आगे कहा कि याद रखें, आपको क्रीज तभी छोड़नी होती है जब गेंदबाज के हाथ से गेंद निकल जाए. उनके इस सुझाव का पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि फ्री बॉल को डॉट बॉल माना जाना चाहिए और अगर उस पर विकेट गिरता है, तो जरूर गेंदबाज के खाते में वह विकेट जुड़ना चाहिए।

मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं अश्विन

सिडनी। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अभी तक 78 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इस दौरान उन्होंने 409 विकेट लिए हैं। इस 34 वर्षीय गेंदबाज को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रैड हॉग ने दावा किया है, कि वह बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं, और महान श्रीलंकाई मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। मुरलीधरन के टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। समय के साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आई है लेकिन वह गेंद से काफी घातक हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं अश्विन को कम से कम 600 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेते हुए देखता हूं। वह शायद मुरलीधरन (800 टेस्ट विकेट्स) के रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और घरेलू टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ अश्विन का प्रदर्शन शानदार रहा है।

श्रीलंकाई खिलाड़ियों को शिकायत करने की जगह मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए : डी सिल्वा

कोलंबो, (एजेंसी)। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मौजूदा क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अरविंद डी सिल्वा ने कहा है कि मौजूदा खिलाड़ियों के अनुबंध के बारे में शिकायत करने की जगह मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए। इसके पहले श्रीलंका के खिलाड़ियों ने नए खिलाड़ियों की अनुबंध प्रणाली को लेकर कहा था कि यह पारदर्शी नहीं है। नई अनुबंध प्रणाली मुख्य रूप से तकनीकी समिति द्वारा तय की गई थी, जिसके प्रमुख डी सिल्वा और साथ ही क्रिकेट टॉम मूडी के निदेशक थे। डी सिल्वा ने कहा कि खिलाड़ियों के सामने पेश करने से पहले हमलोगों ने मामले पर गहराई से चर्चा की। अतीत के विपरीत, हमने लाभ को तीन गुना बढ़ाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डी सिल्वा ने बताया कि खिलाड़ियों को 1,50,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा जो पहले 50,000 अमेरिकी डॉलर तक सीमित था। इस पूरी टीम द्वारा सामूहिक प्रयास करना होगा।

सिल्वा ने कहा कि हमने टी-20 फॉर्मेट के लिए एक स्लैब भी पेश किया, जो अधिकतम 50,000 अमरीकी डॉलर तक चलता है, जिसका पहले कोई पुरस्कार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्हें बीच में आना चाहिए और सकारात्मक क्रिकेट खेलना चाहिए और शिकायत करने के बजाय देश के लिए खेल जीतना शुरू करें। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने क्षेत्र के कुछ अन्य देशों की तरह उन्हें और अधिक लाभ देने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि टीम अपनी वैल्यू बनाती है,तब उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा।

सुरक्षित ओलंपिक आयोजन के लिए जापान में बढ़ाया जाएगा आपातकाल

टोक्यो, (एजेंसी)। जापान टोक्यो में कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए आपातकाल को बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि संक्रमण अभी तक उस स्तर तक धीमा नहीं हो रहा है कि देश 50 दिन के अंदर ओलंपिक खेलों की सुरक्षित मेजबानी कर सके। जापान के वरिष्ठ मंत्री याशुतोशी निशिमुरा ने कहा कि आपात स्थिति को बढ़ाने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में अब भी काफी लोग सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं। उन्हें डर है कि आपात स्थिति को हटाते ही संक्रमण फिर से बढ़ जाएगा।

जापान की राजधानी और आठ अन्य शहरों में मौजूदा आपात स्थिति अगले सोमवार तक खत्म होनी थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अस्पतालों में अब भी काफी कोविड-19 संक्रमित मरीज आ रहे हैं और हाल में गंभीर मामलों की संख्या भी काफी रही थी। निशिमुरा ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने नौ क्षेत्रों में 20 दिन के लिए आपात स्थिति को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो 20 जून तक होगा जिसे विशेषज्ञों से शुरूआती मंजूरी मिल गई है। ओकिनावा में 20 जून तक आपात स्थिति जारी रहेगी।

ओलंपिक आयोजकों को इस तारीख तक फैसला करना होगा कि वे किसी भी दर्शक को अनुमति देंगे या नहीं, क्योंकि विदेशी दर्शकों को महीनों पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जापान के एथलीटों के टीकाकरण में भी देरी हो रही है।

दोहा में डायमंड लीग एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं की 3.000 मीटर रेस में आगे निकलने की होड़ में केनिया की नोराह।

कॉनवे के नाबाद अर्धशतक से मजबूत हुई टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने की संभावना

लंदन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने एजेस बाउल में लाथम इलेवन और विलियमसन इलेवन के बीच न्यूजीलैंड के इंट्रा-स्क्वाड अभ्यास मैच के पहले दिन नाबाद अर्धशतक बनाकर अगले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने की अपनी संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। कप्तान टॉम लाथम और कॉनवे ने टिम साउदी, जैकब डफी, मिचेल सेंटनर और नील वैगनर की मौजूदगी वाली गेंदबाजी के खिलाफ लाथम इलेवन के लिए शुरूआती विकेट के लिए 106 रन जोड़े। दरअसल कॉनवे दूसरे सलामी बल्लेबाज के स्थान के लिए टॉम ब्लंडेल और विल यंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

छोटे प्रारूपों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि शीर्ष क्रम में लाथम के साथ बल्लेबाजी करना उनके लिए सीखने का अच्छा अनुभव था। सौभाग्य से हम दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा किए जा रहे कुछ कामों को पूरा कर सका। वह बहुत अनुभवी हैं और अपने खेल को बखूबी जानते हैं। 29 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि न केवल आज के मैच में, बल्कि प्रशिक्षण और अनुशासन में, शॉट चयन में और जिस तरह से लाथम अपना खेल खेलते हैं, उससे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है।

उनके साथ विकेट के दूसरे छोर पर होना काफी रोमांचक था और पूरे दिन अच्छी सीख थी। केन विलियमसन गली क्षेत्र में खड़े होकर मुझे बल्लेबाजी करते हुए देख रहे थे, जो बहुत भयभीत करने वाला था।

विराट से ज्यादा शास्त्री की है टीम इंडिया, पनेसर ने आस्ट्रेलिया से हालिया जीत का श्रेय शास्त्री को दिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीनों में टीम का प्रदर्शन दिखाता है कि यह विराट कोहली से कहीं ज्यादा शास्त्री की टीम इंडिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हालिया टेस्ट सीरीज में मिली जीत का श्रेय शास्त्री को दिया। उन्होंने कहा विराट कोहली की गैरहाजिरी में शास्त्री ने टेस्ट सीरीज में पिछड़ने के बावजूद टीम इंडिया में जोश भरा और इसकी का नतीजा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। पनेसर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में हुए पहले टेस्ट में टीम इंडिया 36 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद कप्तान कोहली भी निजी वजह के कारण घर लौट गए थे।

टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में आ गई थी। ऐसी स्थिति में जब टीम पहले में टेस्ट बुरी तरह हारी हो, वहां से वापसी करना वाकई चमत्कारिक था। क्योंकि एक-एक कर कई अहम खिलाड़ी भी चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए थे। इसके बावजूद शास्त्री ने टीम इंडिया में ऐसी जान फूंकी कि उसने चार टेस्ट की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने भी टीम इंडिया की सफलता का राज खोला था। उन्होंने बताया कि कैसे रवि शास्त्री के एक मंत्र ने पूरी टीम का विश्वास बढ़ा दिया कि फिर टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल, उस समय शास्त्री ने टीम बैठक में सभी खिलाड़ियों को एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में टीम के 36 रन के कुल स्कोर को एक बैज की तरह सीने पर लगाए रखने का मंत्र दिया था। वह चाहते थे कि टीम का हर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मिले इस जख्म को याद रखे। उनका यह फॉर्मूला काम कर गया और टीम इंडिया ने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। टीम इंडिया फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की तैयारियों में जुटी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथैम्प्टन में डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाना है। भारत ने डब्ल्यूटीसी के तहत कुल 17 टेस्ट खेले थे। इसमें उसने 12 जीते और 4 गंवाए थे, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। वहीं, न्यूजीलैंड ने 7 टेस्ट जीते और 4 हारे थे। अंक तालिका में टीम इंडिया पहले स्थान पर थी।

जींस टी शर्ट में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे एमएस धोनी, पुरानी तस्वीर हो रही वायरल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें या वीडियो अकसर वायरल होते रहते हैं। इस बीच धोनी की पत्नी साक्षी ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वह बच्चों के साथ विकेटकीपिंग करती नजर आ रही हैं। साक्षी ने बताया कि यह फोटो सन 2009 की है। साक्षी ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा-पुराने में से धमाका. आप लोग बड़े क्यों हो गए इसके साथ ही उन्होंने 2009 भी लिखा। धोनी ने सन 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और वह जल्दी ही अपनी धमाकेदार पारियों के चलते स्टार खिलाड़ी बन गए थे। साक्षी ने जो फोटो शेयर की है, वह धोनी के पदार्पण के करीब पांच साल बाद का है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 14वां सीजन बीच में स्थगित होने के बाद सभी खिलाड़ी अपने-अपने घर लौट गए हैं। धोनी रांची में अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। धोनी का एक वीडियो भी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वह जमीन पर लेटे अपने घोड़े चेतक की मालिश करते नजर आ रहे हैं. पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी ने अपने करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। धोनी ने वनडे में 10773 और टेस्ट में 4876 रन बनाए हैं। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में कुल 1617 रन बनाए।

सीआईएसएम के साथ एआईबीए के बीच हुआ समझौता

लुसाने, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद (सीआईएसएम) के साथ आपसी सहयोग के लिए समझौता किया है, जिसके तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त अभ्यास शिविरों का आयोजन करने के साथ एक अकादमी भी स्थापित करेंगे। आपसी सहयोग के इस समझौते में एक संग्रहालय खोलने की योजना भी है।

सीआईएसएम के अध्यक्ष कर्नल हर्व पिसीरिलो ने एआईबीए के साथ जारी संयुक्त बयान में कहा कि यह हमारे और पूरे सैन्य जगत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मुक्केबाजी से सेना में हम सभी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, यह प्रत्येक सैनिक के अभ्यास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी एक जीवनशैली है, यह दुनिया भर में युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय है। सीआईएसएम ने हमेशा इसके विकास पर ध्यान दिया और इस साल हम मास्को में 58वीं सैन्य विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। एआईबीए अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा सीआईएसएम एक बड़ा और महत्वपूर्ण संगठन है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि सेना में मुक्केबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

टोकियो में एशियन क्वालिफिकेशन सूकर मैच के दौरान म्यांमार के खिलाफ पेनाल्टी किक लेते जापान के ओसाको।

धोनी से पंत की तुलना पर भड़के कोच तारक सिन्हा, कहा थोड़ा धीरज रखिए-उसका भी समय आएगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में किसी भी घरेलू क्रिकेट कोच ने तारक सिन्हा जितने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं तैयार किए हैं। दिल्ली में सोनेट क्लब चलाने वाले तारक ने शिखर धवन, आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। हाल के दिनों में ऋषभ पंत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसका श्रेय भी तारक सिन्हा को ही जाता है। तारक ने पंत की महेंद्र सिंह धोनी से तुलना किए जाने का विरोध किया। सिन्हा से जब बीते 6 महीने में पंत के खेल में आए बदलाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पंत हमेशा से मानसिक रूप से मजबूत रहे हैं। वह क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली से रूड़की आए और हमेशा से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहते थे।

उनके चेहरे पर मजबूत इरादा साफ नजर आता है। क्रिकेट आपकी इच्छाशक्ति का खेल है। भले ही आपमें कौशल की कमी हो या कुछ तकनीकी खामी हो, अगर आपके पास दृढ़ इच्छाशक्ति है, तो आप अधिकांश चुनौतियों से पार पा सकते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि अगर पंत को मौका दिया गया तो वो खुद को साबित कर देंगे। करियर के शुरूआत से ही पंत की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से होती रही है। क्या धोनी से तुलना ने पंत को प्रभावित किया है इस सवाल के जवाब में कोच तारक ने कहा कि रोहन गावस्कर खराब खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा याद दिलाया जाता रहा कि वह अपने पिता के आस-पास भी नहीं है। पंत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

पंत की जिस तरह धोनी से लगातार तुलना की गई और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर कोई और खिलाड़ी होता तो कब का टूट गया होता लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पंत की इच्छाशक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के दम पर वह अपने खेल पर फोकस कर पाए हैं।

धोनी जब टीम में आए थे, तो वह काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते थे, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने खेल में बदलाव किया। क्या आपको लगता है कि पंत भी धोनी के ही नक्शेकदम पर चलेंगे इस पर तारक सिन्हा ने कहा कि इसमें किसी को शक नहीं है कि पंत गेमचेंजर और तेजी से सीखने वाले खिलाड़ी हैं। बार-बार पंत की धोनी से तुलना क्यों इस पर उन्होंने कहा आपको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि धोनी को दुनिया को यह दिखाने में भी थोड़ा समय लगा कि वह क्या करने में सक्षम हैं। हमें पंत के साथ भी धैर्य रखने की जरूरत है। उसका भी समय आएगा। यह तो अभी शुरूआत है।